



04 - किसी भी सीवर को अमरारण्य नहीं होना चाहिए



05 - मणिपुर की जातीय हिंसा, अधिकारियों की अविन परीक्षा

A Daily News Magazine

इंदौर

शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2024



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित



06 - विधायक ने शाहपुर के एकलव्य विद्यालय पहुंचकर ली मामले की जानकारी



07- गुरुवार को पलकमती नदी राज्य मार्ग पर लगा जाम...

वर्ष 10 अंक 28, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

नवश की तरह उमरना भी तुम्हीं से सीखा

रफ़ता रफ़ता नज़र आना भी तुम्हीं से सीखा

तुम से हासिल हुआ इक

गहरे समुंदर का सुकूत

और हर मौज से लड़ना भी तुम्हीं से सीखा

अच्छे शेरों की परख तुम ने ही

सिखलाई मुझे

अपने अंदाज़ से कहना भी तुम्हीं से सीखा

तुम ने समझाए गिरी

सोच को आदाब अदब

लपज़ ओ मअनी से

उलझना भी तुम्हीं से सीखा

रिश्ता-ए-नाज़ को जाना

भी तो तुम से जाना

जामा-ए-फ़ख़्र पहनना

भी तुम्हीं से सीखा

छोटी सी बात पे खुश

होना मुझे आता था

पर बड़ी बात पे चुप

रहना तुम्हीं से सीखा।

- जेह्दा निगाह

प्रसंगवश

मीनाक्षी लेखी

सभी समुदाय अपने स्वयंसेवी संगठनों का समर्थन करते हैं, जो गरीबों के उत्थान, उनकी फिलॉसफी और सामाजिक कार्य करने के लिए काम करते हैं। हिंदू धर्म, उपरोक्त सभी धर्मों और समाज की सेवा की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों से पहले से ही मौजूद होने के बावजूद, इस तरह के सहयोग और समन्वय के लिए समान मंच नहीं था, जब तक कि 1925 में नागपुर में एक महाराष्ट्रियन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शुरुआत नहीं की गई।

स्वयंसेवक का मतलब निस्वार्थ कार्यकर्ता होता है और आरएसएस के पीछे का विचार हिंदू तरीके से समाज की निस्वार्थ सेवा करना था। संस्थापक ने 'हिंदू समाज की नींव को मजबूत करने और इसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक स्तरों पर चुनौतियों के लिए तैयार करने की जरूरत का अनुमान लगाया।' आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। पक्षपाती व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियानों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इसने वर्षों से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। आरएसएस की स्थापना राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार देने के लिए की गई थी। हमारी सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताएं, जो धर्म, अहिंसा और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित थीं, उपनिवेशवाद के शर में अपनी आवाज़ खो रही थीं। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में मुसलमान, देश के बाकी हिस्सों के समान वंश और डीएनए और जातीयता होने के बावजूद, आश्वस्त थे कि खिलाफत आंदोलन उनके हितों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी दर्शन के विभाजन और शासन के अनुकूल था।

श्रीलंका में अमेरिका और इजरायल को डराने वाले आतंकी गिरफ्तार भारत के खुफिया इनपुट से नाकाम हुआ खतरा, पुलिस ने बढ़ा दी सुरक्षा



कोलंबो (एजेंसी)। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इजरायली और अमेरिकी यात्रियों के संभावित खतरे की सूचना के बाद लोकप्रिय पर्यटन स्थल 'अरुम बे' क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुधवार को अमेरिका और इजरायल ने सर्फिंग के लिए मशहूर इस इलाके से तत्काल दूर चले जाने को कहा था। श्रीलंका में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को इलाके से दूर जाने को कहा। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अरुम बे समेत श्रीलंका के दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के लिए अपनी यात्रा सलाह को उच्चतम स्तर (लेवल 4) पर कर दिया।

आरएसएस ने एक राष्ट्रवादी आंदोलन के तत्वावधान में भारत के लोगों को एक सांस्कृतिक छत्र के नीचे एकजुट करने का प्रयास किया और यह उन अभिजात्य लोगों को बहुत पसंद नहीं आया, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को त्याग कर अपनी विदेशी शिक्षा और पश्चिमी मूल्यों के संपर्क में पश्चिम की नकल करने के पक्ष में थे। अपनी समृद्ध विरासत से मुह मोड़ते हुए उन्हें यकीन दिलाया गया कि भारतीय मूल्य आदिम और पिछड़े हैं और देश को केवल हिंदू जीवन शैली की निंदा करके ही बचाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि सांस्कृतिक रूप से, इस गौरवशाली प्राचीन धरती के सभी निवासी एक ही सांस्कृतिक पहचान और वंश के हैं। उन्होंने 'हिंदुत्व' की विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसका अर्थ है हिंद (सिंधु) नदी के पार की ज़मीन) के लोग। इस विचारधारा का उद्देश्य जाति, पंथ, रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना, सांस्कृतिक रूप से जुड़े इन सभी लोगों को एकजुट करना था। आरएसएस की नींव वैदिक परंपराओं से प्रेरित अनुशासन और समर्पण में निहित है। 1925 में नागपुर में पहली शाखा स्थापित होने के बाद पूरे देश में शाखाएं बनाई गईं। उन्होंने युवाओं को एक 'असेंबली' प्रकार की सभा में इकट्ठा करके अनुशासन को बढ़ावा दिया, जहां वह स्वदेशी खेलों में शामिल हुए, सूर्य नमस्कार के माध्यम से योग किया, प्रवचन (विद्वान लोगों द्वारा सकारात्मक प्रवचन) सुने और फिर राष्ट्रीय या स्वयंसेवक गान गाया, जो सभी स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित 'सुबह की सभा' की प्रणाली के समान था।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी चर्चा होती थी, जिससे 'स्वयंसेवकों' को समसामयिक मामलों और राजनीति से परिचित होने का अवसर मिलता था।

बैठकें भारत माता की जय या मातृभूमि की जय के एक गूंजते गैर-सांप्रदायिक नारे के साथ समाप्त होती थीं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चिमीकृत अभिजात्य नेता अंग्रेजों के साथ घुलने-मिलने और अपने स्वयं के इतिहास का तिरस्कार करने में व्यस्त थे। पश्चिमी मीडिया ने आरएसएस विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा दिया, उन्हें गाय की पूजा करने वाले, धूप सेकने वाले विधर्मियों के रूप में चित्रित किया, वहीं विचारधाराएं अब पश्चिम में आवाज उठा रही हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आरएसएस को बहुत अधिक हावी होने के लिए दंडित किया गया। नवजात संगठन होने और इसके सदस्यों में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के हिंदू शामिल होने के कारण, आरएसएस के पास कभी भी अपने खिलाफ स्थापित किए गए नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे।

आरएसएस की स्थापना इस प्राचीन धरती के इतिहास और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर एक सांस्कृतिक ध्वज के तहत राष्ट्र और भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ावा देना और अपनी परंपराओं में खुद को स्थापित करते हुए अपनी चिरकालिक मान्यताओं पर गर्व की गहरी भावना को बढ़ावा देना था। आरएसएस की स्थापना के सी बरस बाद, हेडगेवार की बात सही साबित हुई है क्योंकि आज दुनिया हिंदू धर्म के सिद्धांतों को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में स्वीकार करती है और पश्चिम के लोग भारत के दर्शन को अपना रहे हैं। योग हमारा सबसे बड़ा निर्यात है और लैटिन अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के दूर-दराज के कोनों में योग दिवस मनाया जाना उत्साहजनक है। हिंदू दिव्य मंत्र 'ऊँ' का आदिम ध्वनि के रूप में उच्चारण दुनिया भर में गूंज रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया को भारत की खान-पान की

आदतों को अपनाना चाहिए।

जैसा कि हम देखते हैं कि आधुनिक समय के मूल्य हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधाराएं और भी अधिक मूल्यवान हैं। हमारे समाज का ताना-बाना नशीली दवाओं, प्रदर्शनवाद, ताक-झांक, पोंन - सभी सामाजिक बीमारियों से छिन्न-भिन्न हो रहा है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। आरएसएस के अनुशासन को अपनाना और भी जरूरी हो गया है। शाखाओं में भारतीय मूल्यों को शामिल किया जाता है और युवाओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाता है।

संघ कई अलग-अलग सामाजिक गतिविधियों में लगा हुआ है। आरएसएस आज एक लाख से ज्यादा प्रकल्प चलाता है। इन प्रकल्पों के तहत स्वच्छता से लेकर जलवायु परिवर्तन, शिक्षा से लेकर सशक्तिकरण और स्वास्थ्य से लेकर पानी तक के काम किए जा सकते हैं। ये सभी प्रकल्प स्वैच्छिक सेवाएं हैं और ऐसी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए समुदाय की मजबूत स्वयंसेवी भावना है।

इन सभी प्रकल्पों या सेवा गतिविधियों में महिलाओं की मौजूदगी के अलावा आरएसएस की एक बहुत मजबूत महिला शाखा भी है। राष्ट्र सेविका समिति के अंतर्गत महिलाओं को अलग से संगठित किया गया है, जिसका अपना कार्य क्षेत्र है, परिवार प्रबंधन से लेकर मेधावी सिंधु सृजन तक। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां स्वयंसेवक या सेविकाएं मौजूद न हों और इसलिए यह कहना उचित ही है कि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सेवा और कार्य करके मां भारती की सेवा कर रहे हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

अबकी दक्षिण भारत से अपना नया अध्यक्ष चुनेगी बीजेपी!

पार्टी ने शुरू किया मंथन, दिसंबर में हो सकता है ऐलान

अब तक दक्षिण भारत से रह चुके हैं तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर लें, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से तीन शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये हैं:बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णामूर्ति और वेंकैया नायडू। पीएम मोदी के दो कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत के रहे। फिलहाल भाजपा के दक्षिण के दिग्गज नेताओं में प्रहलाद



जोशी, एल मुरुगन, जी. किशन रेड्डी, के. अन्नामलाई, के. ईश्वरप्पा, निर्मला

सीतारामण शामिल हैं। हो सकता है कि पार्टी इन्हीं से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी

साल जनवरी में खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए जून तक विस्तार दिया गया था। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संसदनात्मक चुनाव की जरूरत होती है। इसमें 6 महीने का समय लगता है। इसलिए जून में नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह

54 लाख बच्चों के लिए 324 करोड़ रुपए गणवेश राशि अंतरित की जाएगी

प्रशासन अकादमी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे 14 शिक्षकों का सम्मान

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। समारोह में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्रार्थमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जायेगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 25 अक्टूबर को भोपाल के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती हॉल में प्रातः 10:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि 25 हजार रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विगत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11 हजार



रुपये, शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय इम्पायर अवॉर्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक मार्मा को 25 हजार रुपये की विशेष सम्मान निधि राष्ट्रीय स्तर पर पाँचवे स्थान पर रहीं बालाघाट जिले के शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि लांजी की छात्रा सुश्री शिरोमणी दहीकर

तथा 31वीं स्थान प्राप्त करने वाले भोपाल जिले के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी श्री आरुष नाग को 15-15 हजार रूपयों की विशेष सम्मान निधि प्रदान की जायेगी। इन विद्यार्थियों के साथ ही उनके गाइड शिक्षकों को भी सम्मानित किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T-4 एंजेक्शन के द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय सी.एम. राइज विनोबा रतलम के शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तर की शैक्षिक संगोष्ठी से चयनित प्रथम प्रतिभागी को 11 हजार रुपये, द्वितीय प्रतिभागी को 7 हजार एवं तृतीय को 5 हजार रुपये राशि के साथ शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भी होंगे सम्मानित- शिक्षक सम्मान समारोह में पिछले वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 से सम्मानित प्रदेश के चयनित शिक्षकों का भी सम्मान किया जायेगा। इन्में श्रीमती सारिका घारू माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल सांडिया, होशंगाबाद और रतलम की श्रीमती सीमा अग्निहोत्री शिक्षक सीएम राइज स्कूल विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।

माहिम से चुनावी 'इम्तिहान' में उतरे अमित ठाकरे

● मगर महाराष्ट्र में फेल-पास उनके पापा राज ठाकरे होंगे

मुंबई (एजेंसी)। आदित्य ठाकरे के बाद ठाकरे फैमिली की तीसरी पीढ़ी का एक और सदस्य ने चुनावी राजनीति में डेब्यू किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले माहिम सीट से टिकट दिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि चुनावी इम्तिहान में अमित ठाकरे को उतारकर राज ठाकरे अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। शिवसेना के युथ विंग के प्रमुख के तौर पर राज ठाकरे ने मुंबई को शिवसेना का किला बनाया था। उद्धव ठाकरे के सक्रिय होने से पहले राज ही मुंबई में पार्टी को डील करते थे। आज भी मनसे का जनाधार मुंबई में है। यह भी तय है कि अगर अमित जीत जाते हैं तो वह न सिर्फ मनसे पार्टी और राज के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। अमित ठाकरे के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर शिंदे सेना और उद्धव सेना के उम्मीदवारों से उनका मुकाबला होगा।



डीएमके के भारत के नक्शे में अक्साई चीन-पीओके गायब

विवाद बढ़ने पर हटाया

बीजेपी का आरोप-स्टालिन की पार्टी देश से विश्वासघात कर रही

चेन्नई (एजेंसी)। भाजपा ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी पर देश की संप्रभुता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। दरअसल डीएमके की यूथ विंग ने सोशल मीडिया पर भारत का नक्शा शेयर किया था, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन शामिल नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद डीएमके ने इसे एक्स से हटा लिया है।

अपरकास्ट, ओबीसी और एससी का बनाया मिलाजुला संतुलन

● यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने खेला 'आरएसएस' वाला बड़ा दांव

● आरएसएस का फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट का भी लिया सहारा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गुरुवार को वो दिन आ ही गया, जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई। कुल 10 खाली सीटों में मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई, मीरापुर सीट पर रालोद प्रत्याशी के लिए छोड़ दिया और सीसामऊ पर अभी भाजपा प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। बाकी 7 सीटों पर टिकट बंटवारे में भाजपा की तरफ से जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है, उससे यह तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही पार्टी की तरफ से ग्राउंड फीडबैक का भी अहम योगदान है। यूपी में उपचुनाव



की 7 सीटों पर भाजपा ने काफी मजबूत के बाद टिकट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। इसमें अपरकास्ट के साथ ही पिछड़े और दलित वर्ग का ख्याल भी रखा गया है। भाजपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, जो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया है, जो कि ब्राह्मण हैं। अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट से दलित उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं मैनपुरी की करहल सीट से अनुजेश यादव और प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल को टिकट मिला है। अकबरपुर की कटेही सीट से धर्मराज निषाद को टिकट दिया है।

● सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास, वफादारों को तरजीह- ओबीसी में भी यादव, पटेल, निषाद और मौर्य के जरिए भाजपा ने राजनीतिक लिहाज से अहम पिछड़े वर्ग के अलग-अलग वर्ग को साधने का प्रयास किया है। अभी सात सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। मीरापुर (मुजफ्फरनगर) और सीसामऊ (कानपुर) विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित करने बाकी हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने गठबंधन के तहत मीरापुर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी है। रालोद तय रणनीति के तहत आखिरी समय में अपना पता खोलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीते दिनों में यूपी में सक्रिय हुआ।



जल संरक्षण पर मेपकास्ट का सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन

2030 तक देश में जल की मांग दोगुनी हो जाएगी और वर्ष 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा : डॉ. वी. के. पाराशर

भोपाल। 'वर्ष 2030 तक देश में जल की मांग दोगुनी हो जाएगी एवं 2025 में पूरे विश्व की एक तिहाई जनसंख्या के लिए जल संकट की समस्या होगी'। यह कहना है एम वी एम के पूर्व प्राध्यापक एवं हइड्रोलॉजिस्ट डॉ. वी. के. पाराशर का जो कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) द्वारा सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित एक्सपर्ट लेक्चर में बोल रहे थे। अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि भारत के 25 बड़े शहरों में जल संकट गंभीर रूप से सामने आएगा। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा हर प्रदेश में जल प्रबंधन हेतु



कम्पोजिट वाटर मेनेजमेंट इंडेक्स बनाया गया है जिसके अंतर्गत 28 प्रकार के पैरामीटर स्थापित किया गया है जो कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों में जल की गंभीर समस्या है और वर्ष 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि चेन्नई एवं बेंगलुरु जैसे शहरों में एवं उनके आस पास के लगभग सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। उन्होंने बताया कि विश्व का 97.2 प्रतिशत जल समुद्री है एवं केवल 2.80 प्रतिशत शुद्ध जल उपलब्ध है। भारत के पास विश्व जल स्रोत का 4 प्रतिशत है। भारत में जल

135 लीटर प्रति व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है एवं वाटर हार्वैस्टिंग स्यस्टम से जल का प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में मेपकास्ट के क्लिएटिव लर्निंग सेंटर के समन्वयक श्री पंकज गोथरा भी उपस्थित थे उन्होंने जल आधारित तकनीकी एवं प्रादर्शों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र बिहारी गोस्वामी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की समन्वयक इको क्लब की प्रभारी डॉ दीप्ति संकत थीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्राध्यापक एवं छात्राएं उपस्थित थीं।

संक्षिप्त समाचार

प्रियंका गांधी ने अपने पास बताई 12 करोड़ की संपत्ति

पति 66 करोड़ के मालिक



नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हलफनामा में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4.24 करोड़ रुपए की चल और 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्योरा दिया है। वाड्रा के पास कुल 65.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37.9 करोड़ रुपए और अचल संपत्तियां 27.64 करोड़ रुपए की हैं।

गांदरबल हमले के आतंकी की तस्वीर आई सामने

7 लोगों की जान गई थी

गांदरबल (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर की देर रात आतंकी हमला हुआ था। इसमें 7 लोगों की जान गई थी। बुधवार को इस हमले में शामिल आतंकी की तस्वीर सामने आई। हाथ में एके-47 जैसी राइफल लिया हुआ आतंकी किसी



इमारत में घुसता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी की पहचान फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था।

भारत से जान का खतरा, अमेरिका में हुई हत्या की कोशिश

आतंकी पन्नु बोला-

3 दिन पहले पलाइट्स में ब्लास्ट की धमकी दी थी

जालंधर (एजेंसी)। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नु ने भारत से जान का खतरा बताया है। कनाडाई न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि अमेरिका में भारत सरकार के इशारे पर उसकी हत्या की कोशिश की गई। पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई, इसके बावजूद वह खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बंद नहीं करेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि पन्नु की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक विकास यादव भी शामिल है।

यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेगा नया शहर, तैयारी पूरी

एनसीआर के जिलों को होगा बड़ा फायदा, योगी सरकार का बड़ा प्लान

नोएडा (एजेंसी)। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे योगी सरकार एक नया शहर बसाने जा रही है। इस शहर को हाईटेक सिटी की तर्ज पर बताया जाएगा। इसमें लोगों के लिए ना सिर्फ सभी सुविधाओं से युक्त रहिायशी मकान बसाए जाएंगे बल्कि उद्योगों के लिए भी यहां कई सुविधाएं होंगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मथुरा में राया के पास बसाए जा रहे इस शहर के लिए यमुना प्राधिकरण ने फेज-2 विस्तार के लिए राया अर्बन सेंटर के लिए मास्टर-2031 को यूपी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह शहर करीब 11,653.76 हेक्टेयर में फैला होगा। यूपी सरकार राया अर्बन सेंटर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों ओर तीन-तीन किलोमीटर में बसाने की योजना बना



रही है। मास्टर प्लान-2031 के तहत राया अर्बन सेंटर के नाम से नया शहर बसाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया था। इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। पहले इसे 9366.2 हेक्टेयर में बसाया जाना था लेकिन अब इसका क्षेत्र बढ़ाकर 11,653.76 हेक्टेयर कर दिया गया है।

पेंशनर्स ने केंद्र के समान 53 प्रतिशत डीआर मांगा

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष अमोद सक्सेना ने प्रमुख सचिव वित्त को बिना छग सहमति के केंद्रीय पेंशनर के समान 53 प्रतिशत महंगाई राहत की मांग की है। सक्सेना ने आरोप लगाया है कि विगत 24 वर्षों से दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य सहमति का आदान प्रदान किया जा रहा है जबकि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की अनुसूची 6 में इसका कहीं उल्लेख नहीं है साथ ही महंगाई राहत के संबंध में छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2000 से दी गई सभी सहमतियों में पूर्व मध्य प्रदेश (एकीकृत) के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों का उल्लेख किया गया है।

सक्सेना ने बताया कि महालेखाकार द्वारा भी मध्य प्रदेश से पेंशनरी दायित्वों के प्रभाजन संबंधी सभी पत्रों में भी एकीकृत मध्य प्रदेश का उल्लेख किया जा रहा है एवं मध्य प्रदेश वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2000 के अनुसार 73.38 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन से

वसूल की जा रही है। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया की अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक आधारित वेतन/पेंशन के वास्तविक मूल्य में आई गिरावट की पूर्ति महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के प्रतिशत का निर्धारण कर प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई से भुगतान किए जाने के केंद्रीय आदेश है किंतु प्रदेश के पेंशनरों पर किस माह से कितने प्रतिशत महंगाई प्रभावशील हुई है का संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत वित्त विभाग द्वारा अपने स्तर से आकलन करने के कारण प्रदेश के पेंशनरों को लगातार वित्तीय नुकसान हो रहा है ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्रीय पेंशनरों के समान गणना कर 53 प्रतिशत महंगाई राहत आदेश शीघ्र जारी कर एसोसिएशन को अवगत कराएं। ज्ञापन की प्रतिलिपि सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को देते हुए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संदर्भ में मध्य प्रदेश वित्त विभाग को महंगाई राहत का भुगतान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

दहेज उत्पीड़न के मामलों में बरतें सावधानी बेगुनाहों की रक्षा करें



नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आपसे है। जमानत भी मुश्किल से होती है। कानून पूछा जाए कि 2-4 ऐसे कानूनों का नाम के दुरुपयोग को लेकर समय-समय पर अदालतें भी चिता जताती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए अदालतों को सलाह दी है कि वे दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या से जुड़े मामलों सावधानी बरतें। ध्यान रखें कि कोई बेगुनाह परेशान न हो। अदालतें दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतें।

स्पर्श हिमालय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में संतोष चौबे होंगे विशिष्ट अतिथि

भोपाल। देहरादून के समीप ग्राम थातों में स्थापित लेखक ग्राम में स्पर्श हिमालय फाउण्डेशन द्वारा तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद करेंगे तथा समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। समापन समारोह में विश्व रंग के निदेशक एवं रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के टैगोर अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉ. जवाहर कर्णावट एवं विश्व रंग सचिवालय के सचिव संजय सिंह राठौर को भी विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों और महानुभावों की भागीदारी रहेगी।

वनमाली सृजन पीठ में संतोष चौबे का कहानी पाठ आयोजित



वैश्विक फलक बुनती है। राष्ट्रीय वनमाली सृजन पीठ के विमर्श कक्ष में आयोजित कथा पाठ में वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा, वनमाली सृजन केन्द्र भोपाल की अध्यक्ष डॉ. वीणा सिन्हा, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र के निदेशक वियन उपाध्याय, विश्व रंग सचिवालय के सचिव संजय सिंह राठौर, वनमाली कथा के संपादक, युवा कथाकार कुणाल सिंह, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए के सह-संपादक, युवा कवि मोहन सगोरिया, वनमाली सृजन केन्द्र, भोपाल की सह-संयोजक डॉ. सावित्री सिंह परिहार, चर्चित युवा उपन्यासकार संजय सेफर्ड, युवा कवि मुदित श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता आशा पाठक, युवा रचनाकार वैशाली एवं रवि चौहान ने रचनात्मक भागीदारी की। अंत में आभार कार्यक्रम की समन्वयक वनमाली सृजन पीठ की राष्ट्रीय संयोजक ज्योति रघुवंशी द्वारा व्यक्त किया गया।

पंजाब विधानसभा उपचुनाव इस बार नहीं लड़ेगा एसएडी

पार्टी की वर्किंग कमेटी में हुआ फैसला, कई सालों बाद बनी स्थिति



चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंथक संकट से घिरी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) चार सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यह फैसला आज पार्टी की कार्यसमिति और जिला प्रधानों की बैठक में लिया गया है। करीब दो घंटे चली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसके बाद पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। हालांकि पार्टी एसजीपीसी के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेगी।

उन्होंने कहा कि हम हमेशा श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन करते हैं। 30 अगस्त को प्रधान तनखैया घोषित किए गए। 31 तारीख को वह अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। लेकिन काफी समय बीत चुका था। कई बार सिंह साहिब से फैसला देने का आग्रह किया गया। लेकिन अब चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लोग चाहते थे कि प्रधान गिद्दड़बाहा हलके से चुनाव लड़ें। लेकिन कल जैसे ही जयधर साहब का आदेश आया, यह साफ हो गया कि वह प्रचार नहीं कर सकते।

कन्फेक्शनरी कारोबारी की शिकायत करने दिल्ली से आए व्यापारी

पुलिस से कार्रवाई की मांग, बोले रशिया का नागरिक बताकर हमारे साथ तीन करोड़ की धोखाधड़ी की



इंदौर (एजेंसी)। दिल्ली के तीन व्यापारियों ने बुधवार को इंदौर के एक व्यापारी की पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उन्होंने मोडिया को बताया कि यहां के कन्फेक्शनरी कारोबारी ने हमारे साथ तीन करोड़ की धोखाधड़ी की है। इस संबंध में तीनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला इंदौर के कारोबारी गौरव अहलावत से जुड़ा है। बुधवार को दिल्ली के व्यापारी छोटेलाल पुरी ने पुलिस से शिकायत की। तीनों ने आरोप लगाया कि अहलावत ने रशिया की नागरिकता ले रखी है। वो हमें वहां की सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के नाम से डराता है। अहलावत ने कुछ साल पहले अपनी दिल्ली स्थित कंपनी जीआरवी क्रिएशंस के लिए प्रिटिंग और पैकेजिंग का काम कराया था, जिसके एवज में 50 लाख रुपए देना थे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके बाद उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। देनदारी से बचने के लिए अपना पता भी बदल दिया गया। एक अन्य व्यापारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मेरी फर्म प्राची प्रिंट एंड पैकेजिंग ने बताया कि चारवुड प्लास्टिक और साई कॉर्पोरेशन के नाम से उनकी फर्म है। हमारे यहां से अहलावत ने 30 लाख रुपए के खिलौने लिए और पैसे नहीं चुकाए। इस मामले में इंदौर के कारोबारी गौरव अहलावत ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मामला चार-पांच साल पुराना है। इतने सालों में उन्होंने मुझे एक भी नोटिस नहीं दिया। मैं त्रिपाठी से जुलाई 2019 में मिला था, लेकिन इसके पहले हमारे कारोबारी रिस्ते खत्म हो गए थे। इससे पहले मैं उनसे कभी नहीं मिला।

जनप्रतिनिधियों ने ली बीजेपी की सक्रिय सदस्यता

इंदौर में विधायक मेंदोला बोले- सदस्य बनना देश की आत्मा से जुड़ने जैसा



इंदौर (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान ‘संगठन पर्व’ में देशभर में नंबर वन पर आने वाले इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की सक्रियता सदस्यता लेना शुरू कर दिया है। इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और विधायक गोल्ड शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधी पार्टी की सक्रिय सदस्यता अब तक ले चुके है। इंदौर 2 के विधायक रमेश मेंदोला ने भी पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है। सक्रिय सदस्यता लेने के दौरान मेंदोला ने कहा कि हमारी पहचान संगठन से ही है। संगठन को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। भाजपा का सदस्य बनना देश के मन और देश की आत्मा से जुड़ने जैसा है। सदस्यता प्रभारी सुदर्शन गुप्ता ने बताया कि हमारे जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही इंदौर सदस्यता अभियान में देश में नंबर 1 आया है। वहीं सदस्यता अभियान टोली के सदस्यों ने बताया कि रमेश मेंदोला ने सदस्यता अभियान में विधायकों की सूची में देशभर में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए है।

देर रात डीपी में जा घुसा ऑटो, चालक की मौत

दो दिन पहले ही हुआ था आंखों का ऑपरेशन; घर पर बिना बताए ऑटो लेकर निकला था

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में बुधवार देर रात एक हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। वह सड़क किनारे लगी बिजली डीपी में जा घुसा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के मोबाइल से परिवार को जानकारी दी। तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक प्रवीण (37) निवासी दुर्गा नगर पालदा बुसवार देर रात करीब 12 बजे सड़क हादसे का शिकार हो गया। तेजाजी नगर इलाके में स्थित होमगाई ऑफिस के पास डीपी में उसकी ऑटो रिक्षा टकराई हुई मिली। तत्काल एंबुलेंस से एमबाल भेजा। देर रात इलाज के दौरान यहां उसकी मौत हो गई। मृतक प्रवीण के परिवार में दो बेटियां, पत्नी व मां और छोटा भाई नीलेश है। परिवार के मुताबिक दो दिन पहले ही उसकी एमवाय से छुट्टी हुई थी। आंखों के ऑपरेशन के लिए उस यहां भर्ती किया गया था। परिवार को भी यह जानकारी नहीं थी कि वह ऑटो चलाने लगा था।

इंदौर में तांत्रिक ने की महिला से छेड़छाड़

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के एमआईजी इलाके में एक महिला ने तांत्रिक बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि वह बाबा ने उपचार करने के दौरान उसके साथ गंदी हरकत की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिष्या पुलिस के मुताबिक हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर महिला ने शिकायत की। वह ई-रिक्षा चलाने का काम करती है। तबीयत ठीक नहीं होने पर तीन दिन पहले एक सवारी ने मांगलिया गांव के अब्दुल रजाक बाबा के बारे में बताया। वह हर तरह की बीमारी और बाधा ठीक कर देता है। इसके बाद दवाइयां भी असर करने लगती हैं। मंगलवार 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे बाबा के घर जाकर परेशानी बताई। बाबा ने अगले दिन घर से गेहूं और नीबू साथ लेकर आने कहा। अगले दिन उपचार के दौरान बाबा ने अधिक पैसे खर्च होने की बात कही। पैसे नहीं होने पर मोबाइल पर बातचीत और उसकी बुलाई जगह पर आने को कहा। इसके बाद बाबा ने छेड़छाड़ कर गलत हरकत की। विरोध करने पर बाबा ने जान से मारने की धमकी दी।

इंदौर

इंदौर में पाकीजा का बेसमेंट खाली कराने पहुंचा निगम अमला

रीगल सर्कल स्थित शोरूम पर सुबह-सुबह कार्रवाई, छत पर बने अवैध शेड को भी तोड़ा

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर नगर निगम की टीम गुरुवार सुबह रीगल सर्कल स्थित पाकीजा शोरूम का बेसमेंट खाली कराने पहुंची। यहां बेसमेंट में पार्किंग की जगह कपड़ों का शोरूम खोल रखा था। नगर निगम ने इससे पहले पाकीजा शोरूम के संचालकों को नोटिस दिया था। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में संचालकों ने हाई कोर्ट की शरण लेकर स्टे ले लिया था। इस दौरान शोरूम के संचालकों ने कार्रवाई का विरोध किया और स्टे का हवाला दिया। पर नगर निगम अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट को क्लियर कराया जा रहा है। यहां अधिकांश बिल्डिंग के बेसमेंट में व्यापारियों ने पार्किंग की जगह

दुकानें, शोरूम या ऑफिस खोल रखे हैं। इस वजह से सड़क पर गाड़ियां पार्क होती हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। कार्रवाई के दौरान डिटी कमिश्नर लता अग्रवाल और गीतेश तिवारी सहित दो थानों का पुलिस बल मौजूद था।पाकीजा शोरूम के संचालकों ने स्टे का हवाला दिया लेकिन निगम के अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। दुकानें, शोरूम या ऑफिस खोल रखे हैं। इस वजह से सड़क पर गाड़ियां पार्क होती हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। कार्रवाई के दौरान डिटी कमिश्नर लता अग्रवाल और गीतेश तिवारी सहित दो थानों का पुलिस बल मौजूद था।पाकीजा शोरूम के संचालकों ने स्टे का हवाला दिया लेकिन निगम के अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। दरअसल इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट को क्लियर कराया जा रहा है। यहां अधिकांश बिल्डिंग के बेसमेंट में व्यापारियों ने पार्किंग की जगह



से पैक कर दिया गया है। यानी बेसमेंट पूरा कवर हो गया है, जो किसी घटना-दुर्घटना

के हिसाब से जान-माल के लिए काफी घातक है। इस तरह बेसमेंट का पार्किंग की

इंदौर भाजयुमो उपाध्यक्ष गोयल पर अब धमकाने का केस

क्लब एंड रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव हेड ने दर्ज कराई शिकायत, दो करोड़ के फर्जीवाड़े में भी आरोपी है कपिल

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर की एमआईजी पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल पर एक ओर केस दर्ज किया है। गोयल पर क्लब एंड रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव हेड को धमकाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस अब जल्द ही उसकी गिरफ्तारी करेगी। बता दें कि दो दिन पहले ही कपिल और उसकी पत्नी के खिलाफ एक व्यापारी की शिकायत पर एमजी रोड पुलिस ने दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। टीआई सीबी सिंह ने बताया कि कुलदीप सिंह की शिकायत पर बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल और उसके साथी चंद्रमूल चंदानी के खिलाफ धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

कुलदीप ने बताया कि उसका खुद का रेस्टोरेंट भी है। 13 अगस्त को चंद्रमूल चंदानी के सीओडी क्लब में कुलदीप ने बतौर एग्जीक्यूटिव हेड जॉइन किया था। 20 हजार रुपए सैलरी तय हुई। चंद्रमूल ने अगले माह 20 हजार रुपए भी दिए। लेकिन उसके अगले महीने से सैलरी देने में आनाकानी करने लगा। कॉल किया तो उसने कहा कि आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। रिक्लेस्ट करने पर भी नहीं माना और कहने लगा कि लेकर कोर्ट चले जाओ। इसके बाद चंदानी ने कहा कि कपिल तुम्हें कॉल कर



लेगा। कुलदीप ने जब कहा कि वो कपिल को नहीं जानता और उसके यहां नौकरी नहीं की है।

इस पर चंदानी ने फोन काट दिया। मंगलवार शाम को कपिल ने कुलदीप को कॉल आया। कुलदीप ने अपने दोस्तों सुरेंद्र अरोरा, सुखदीप पटेल और सोनू अहिरवार के सामने स्पीकर पर कॉल उठाया। इस दौरान कॉल काफ्रेंस पर था। उसमें चंद्रमूल चंदानी भी जुड़ा था। कपिल

धमकाने लगा और कहा कि स्कीम नंबर-130 आ जाओ। इसके बाद कहने लगा कि आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? फिर जान से मारने की धमकी दी। जब कपिल से कहा कि तुम्हें नहीं जानता मेरी बात चंदानी से हुई थी, तो कपिल गालियां देने लगा और सिख धर्म को लेकर गलत बातों की। इसके बाद थाने आकर पुलिस को पूरी बात बताई।

इंदौर में दुबई से संचालित होता था सट्टा

क्राइम ब्रांच ने लोकल गैंग के 4 एजेन्ट को पकड़ा; लैपटॉप, मोबाइल सहित करोड़ों का हिसाब मिला

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन गेमिंग एप से सट्टा चलाने वाली गैंग के चार एजेन्ट को पकड़ा है। आरोपी पलसीकर कॉलोनी के एक घर में बैठकर सट्टा लगा रहे थे। उन्होंने कई शहर के लोगों को आईडी दी हुई थी। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोटिया के मुताबिक, दुबई से संचालित ऑनलाइन गेमिंग एप से सट्टा चलाने वाली गैंग के लोकल एजेन्ट सुनील निवासी काटजू कॉलोनी, उसके भाई प्रवीण, विक्की निवासी माणक चौक रतलाम और भूपेंद्र चौरासिया निवासी राधा नगर सदर बाजार को पकड़ा है। आरोपी वेबसाइट पर सट्टा लगा रहे थे। आरोपी वेबसाइट के वैध डॉक्यूमेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पाए। वेबसाइट पर आने वाले पैसों को भी अलग बैंक अकाउंट पर बुलवाते थे। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 कम्प्यूटर, 1 टेलीफोन, वाईफाई राउटर, कैलकुलेटर, नगदी सहित 1 करोड़ से अधिक का ऑनलाइन सट्टे के हिसाब किताब का लेखा जोखा मिला है।पुलिस ने आरोपियों के घर से कई लैपटॉप, कंप्यूटर, और लेखा-जोखा का रिकॉर्ड बरामद किया है।



इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बुधवार कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। नए कुलपति की नियुक्ति के बाद यह पहली बैठक थी। कांग्रेस नेता का आरोप है कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि देवी अहिल्या के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासनिक रिटायर्ड अफसर को ऑब्जर्व बनाया जाएगा। जो की बिल्कुल गलत है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय कल की बैठक में नहीं बल्कि पहले ही हो चुका है। जिसे दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं के लिए अमल में लिया जाएगा।देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के बैठक में नवागत कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंहई का स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने कहा कि इंदौर डीएवीवी कुलपति के प्रारंभिक निर्णय ही अपरिपक्वता के उदाहरण बन गये हैं। डीएवीवी की

नए पुलिस कमिश्नर के सामने कई चुनौती

इंदौर में थानों का सिस्टम सुधारना, नशे पर नियंत्रण और बदहाल ट्रैफिक



पर सख्ती नहीं कर पाता।

3. ड्रस पर नियंत्रण: बीते कुछ सालों में मुंबई, गुजरात और राजस्थान से कई ड्रग माफिया इंदौर को सेंट्रल पॉइंट बनाकर नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। मोहल्ले, बस्तियों के अलावा पब-बार में बेखोफ पैडलर सक्रिय हैं।

4. क्राइम ब्रांच का स्वरूप बदलना: पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से क्राइम ब्रांच कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है। हत्या, अंधे कत्ल, ड्रग माफिया के संगठित गिरोह और डिजिटल अरेस्ट के प्रकरणों में कोई गैंग व आरोपी नहीं पकड़ा। केवल छोटे-मोटे ड्रग पैडलर व अपराधी पकड़ में आए।

5. रात्रि गश्त व्यवस्था ठप: सिर्फ वीक एंड पर पुलिस सड़कों पर नजर आती है। वह भी कुछ

एक स्थानों पर। चोरी, लूट और छेड़छाड़ की घटनाओं से आमजन परेशान है।

6. नशाखोरों पर सख्ती नहीं: रात होते ही नशाखोर बदमाश सक्रिय हो जाते हैं। परिवार के साथ निकलने वालों को तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने वालों से खतरा रहता है। ऐसे बदमाशों पर सख्त पुलिसिंग की जरूरत होगी।

7. महिला अपराध: महिला व लैंगिंग अपराध बढ़ रहे हैं। सेक्स ऑफेंडर्स व नाबालिगों से वारदातें करने वाले बदमाशों पर कंट्रोल करना होगा।

8. फील्ड पुलिसिंग की दरकार: कमिश्नरी लागू होने के बाद अफसरों की फील्ड पुलिसिंग कम हुई है। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में जनता से सीधे कभी नहीं जुड़े। इसे सुधारने की जरूरत है।

9. पुलिस जनसुनवाई: प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई से जनता का मोह भंग हो गया है। क्योंकि, अफसर जो भी कार्रवाई के निर्देश देते हैं, थाने जाने पर पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता।

10. अफसरों में सामंजस्य की कमी: चार जोन में बैठे अफसरों में सामंजस्य नहीं दिखता। मनमुटाव व मनमानी से लोग परेशान है।

नए कुलपति की राज्यपाल से शिकायत

कांग्रेस ने रिटायर्ड अफसर को ऑब्जर्वर बनाने के निर्णय का किया विरोध, बताया-आदिवासी विरोधी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बुधवार कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। नए कुलपति की नियुक्ति के बाद यह पहली बैठक थी। कांग्रेस नेता का आरोप है कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि देवी अहिल्या के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासनिक रिटायर्ड अफसर को ऑब्जर्व बनाया जाएगा। जो की बिल्कुल गलत है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय कल की बैठक में नहीं बल्कि पहले ही हो चुका है। जिसे दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं के लिए अमल में लिया जाएगा।देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के बैठक में नवागत कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंह यादव ने स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने कहा कि इंदौर डीएवीवी कुलपति के प्रारंभिक निर्णय ही अपरिपक्वता के उदाहरण बन गये हैं। डीएवीवी की

प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले निर्णय करने की जगह सस्ती लोकप्रियता बढ़ाने वाले निर्णय लेना संदेहास्पद है। यादव का कहना है कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी सहित प्रदेशभर की सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूजी-पीजी परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की सख्त गाइडलाइन 2022 लागू है। इसके तहत यूनिवर्सिटी को अब परीक्षा के दौरान ऑब्जर्वर बनाना होगा। यह उन केंद्रों पर तैनात होंगे जहां नकल की शिकायतें ज्यादा आती हैं या लगातार कुछ सालों से नकल के मामले सामने आते रहें हैं।

उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अंतर्गत सिर्फ शासकीय कॉलेज की फैकल्टी को ही ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे। विभाग द्वारा जारी आदेश में



स्पष्ट है कि अनुदान प्राप्त सारे कॉलेजों में परीक्षा के दौरान शासकीय कॉलेज की फैकल्टी को ही ऑब्जर्वर के तौर पर ड्यूटी पर लगाया जाएगा। यहीं नहीं शासकीय, अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों में ड्यूटी लगातार बदलना होगी। कोई भी फैकल्टी

अपने ही कॉलेज में ऑब्जर्वर के तौर पर ड्यूटी नहीं दे पाएंगे, उन्हें अन्य कॉलेज में जाना होगा।यह व्यवस्थाएं सख्ती से लागू रहेंगी।

वर्तमान कुलपति ने नियमों की जानकारी के निजी कॉलेजों के दबाव में नकल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक रिटायर्ड अफसर को ऑब्जर्वर बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे निजी कॉलेज के संचालक हैं, जो खुलेआम नकल कराना चाहते हैं। ऐसी सूचना है कि रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों की सूची भी निजी कॉलेज संचालकों ने बनाकर कुलपति को सौंप दी हैं। सोच समझकर षड्यंत्र के अंतर्गत यह निर्णय कुलपति ने उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विरुद्ध किया है।

संपादकीय
ब्रिक्स सम्मेलन का हासिल
रूस के कजान में सम्पन्न दो दिनी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने और विश्व में अमेरिका व पश्चिमी देशों की दादागिरी व डॉलर के दबदबे को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। सम्मेलन में शामिल सभी 9 देशों ने लोकल करेंसी में आपसी व्यापार पर सहमति जताई है। इस लिहाज से भारत अब ब्रिक्स देशों के साथ रूपए पर व्यापार कर सकेगा। सम्मेलन के इस फैसले से वैश्विक मार्केट में डॉलर को बड़ी चुनौती मिलने की संभावना है, क्योंकि ज्यादातर वैश्विक व्यापार डॉलर में ही होता है। 1 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि सदस्य देश कामकाज के स्तर पर स्थिरता बनाये रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों की संभावना तलाशेंगे। ब्रिक्स नेताओं ने 21वीं सदी में मानव जीवन के सभी पहलुओं की तेज गति वाली डिजिटलीकरण प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की और विकास के लिए डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका और इस मुद्दे के समाधान के लिए ब्रिक्स के भीतर जुड़ाव को तेज करने की जरूरत बताई। इसके अलावा सदस्य देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय निपटान की व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई। साथ ही स्वतंत्र रूप से काम करने वाला सीमापार निपटान और डिपॉजिटरी बुनियादी ढांचे की व्यावहारिकता का अध्ययन करने और ब्रिक्स पुनर्बीमा कंपनी पर भी सहमति व्यक्त की। सदस्य देशों के नेताओं ने 2 1वीं सदी में नव विकास बैंक को एक नये प्रकार के बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) के रूप में विकसित करने पर भी सहमति जताई और ब्रिक्स के नेतृत्व वाले बैंक की सदस्यता को बढ़ाने का समर्थन किया। ब्रिक्स घोषणा में कहा गया है कि हम व्यापार बाधाओं को कम करने और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के सिद्धांत पर तैयार तेज, कम लागत वाले, कुशल, पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी सीमापार भुगतान उत्पादों के व्यापक लाभ को समझते हैं। हम ब्रिक्स देशों और उनके व्यापारिक भागीदारों के बीच वित्तीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का स्वागत करते हैं। इसी के तहत सभी सदस्य देश अपना नया बैंकिंग नेटवर्क बनाएंगे। गौरतलब है कि ब्रिक्स के 9 सदस्य हैं तथा सउदी अरब उसका आमंत्रित सदस्य है। जहां तक भारत की बात है तो उसने अपनी सफल कूटनीति के जरिए पूर्व और पश्चिम के बीच जबर्दस्त संतुलन साधा हुआ है। हम सभी के साथ हैं और शायद किसी के साथ नहीं। हमारे देश के हिसाब से यह सम्मेलन पड़ोसी से विवादों को सुलझाने और दोस्ती के रास्ते पर दो कदम आगे बढ़ने का संदेश लेकर आया है। पांच साल पहले गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते में भी खराबसा आ गइ थी। जिसे इस बार विवादित क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाओं के हटने के फैसले से ढंकने की कोशिश की गई है। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में दोनों देशों द्वारा तनाव कम करने पर सहमत होना बड़ी बात है। इसका प्रेय मोदी सरकार और उनकी टीम को जाता है। सम्मेलन के दूसरे दिन श्रीय राष्ट्रपति पुतिन की भी अहम भूमिका रही है। उम्मीद की जाए कि सौहार्द की यह खिड़की आगे भी खुली रहेगी और चीन पहले की तरह मुंह में राम बाल में छुरी वाले अंदाज में भारत से रिश्ते नहीं खेलेगा। चीन के साथ हाथ मिलाते समय हमें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

विरथापन
राजकुमार सिन्हा

लेखक 'बगी बांध विस्थापित संघ' के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ।

मध्यप्रदेश में आजकल राजधानी भोपाल से लगे हुए रातापानी अभ्यारण्य को 8 वां टाईगर रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है जिसमें 2170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें राज्य के सीहोर और औबेदुल्लागढ़ के वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अंदर 32 गाँवों के दस हजार परिवार निवासरत हैं। दूसरी ओर अलग- अलग ‘टाईगर रिजर्व’ के बीच कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है जिसमें अनेक गाँवों के विस्थापन की संभावना है। इस कॉरिडोर में कान्हा से पेंच टाईगर रिजर्व, पेंच से सतपुड़ा टाईगर रिजर्व और बांधवगढ़ से संजय टाईगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा।

देश के 19 राज्यों के 53 टाईगर रिजर्व से 848 गांव के 89808 परिवारों को ‘टाईगर रिजर्व’ के ‘कोर क्षेत्रों’ से विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें अधिकांश आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अभी तक 257 गांवों के 25007 परिवारों को हटया जा चुका है। विगत 19 जून 2024 को पर्यावरण मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण’ (एनटीसीए) ने एक आदेश जारी किया है। इसमें सभी राज्यों के अधिकारियों को राज्य में घोषित किए गए ‘टाईगर रिजर्व’ के ‘कोर क्षेत्रों’ में मौजूद 591 गांवों और उनके 64801 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित करने का निर्देश शामिल है और इस पर ‘कार्य योजना’ तथा नियमित प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।

‘एनटीसीए’ द्वारा विस्थापन को लेकर उठये गए ये कदम पूर्ण रूप से क़ानून और संरक्षण के ढावों व भावनाओं की अहंतेलना करते हैं और अनेक संबंधित क़ानूनों का उल्लंघन करते हैं। इनमें ‘वन अधिकार क़ानून -2006,’ ‘वन्यप्राणी संरक्षण क़ानून- 1972’ व संशोधित 2006, ‘भू-अर्जन, पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम -2013,’ ‘पैसा क़ानून - 1996,’ ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम- 1989’ शामिल हैं। ‘एनटीसीए’

सुबह सवरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ़्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राखेड्डी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हास्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी संपादक (म.प्र.) - गिरिश उपाध्याय वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल स्थानीय संपादक - हेमंत पाल प्रबंध संपादक - अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा) RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040, Mobile No.: 09893032101 Email- subahsaverenews@gmail.com
‘सुबह सवरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे लगावार एन का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

नजरिया
अनुराग बेहार

लेखक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक वाइस चांसलर हैं। अंग्रेजी अखबार मिंट में प्रकाशित आलेख से अनुवि।

खुला सीवर 10 किलोमीटर तक सीधा बहता है, जो लगभग 8 मीटर गहरे और 50 मीटर चौड़े एक गहरे घाटीनुमा गड्ढे में है और जिसके किनारे इस तरह ढलान लिए हुए हैं कि बीच में इसकी चौड़ाई का 20 मीटर हिस्सा समतल है। 6 मीटर चौड़ा सीवर गड्ढे के इसी समतल हिस्से के बीच में है। इस घाटी के ऊपर 10 किलोमीटर की पूरी लंबाई को घेरता हुआ एक एलिवेटेड हाईवे गुजरता है, जो सीवर से लगभग 20 मीटर ऊपर और घाटी के किनारे की जमीन से लगभग 12 मीटर ऊपर है। एक व्यस्त रेलवे लाइन दक्षिणी छोर के अधिकांश हिस्से के समानांतर चलती है और उत्तरी छोर पर एक सड़क है। ऊपर का हाईवे गड्ढे की पूरी चौड़ाई को कवर करता है। सीवर वाला गड्ढा हाई-स्पीड छह लेन वाले हाईवे से दिखाई नहीं देता क्योंकि यह ठीक हाईवे के नीचे है।

घुमावदार काला कीचड़ सीवर में तेजी से बहता है। यह बीस लाख लोगों की आबादी वाले शहर से आया कचरा है, जो भयानक बदबू लिए आता है। गड्ढे के आसपास लगभग 2000 लोग झुगियाँ बनाकर रहते हैं। ये झुगियाँ बेकार प्लास्टिक, धातु की चादरों और सड़ी हुई लकड़ी से बनी हैं। मानसून की बारिश के दौरान सीवर का बहाव अनियंत्रित हो जाता है इसलिए झुगियाँ ढलान वाले हिस्से के ऊपर की ओर ही बनी हुई हैं, जहाँ से आँखों को कोई बाधा नहीं पहुँचती और ये झुगियाँ गड्ढे के दोनों किनारों से साफ दिखाई देती हैं। सीवर के किनारे जगह-जगह पर, दो-दो वर्ग फुट का शौचालय बनाने हेतु ज़मीन में गड़ी हुई चार बाँस की छड़ियों के चारों ओर फटी हुई साड़ियाँ लपेटी हुई देखी जा सकती हैं।

आसपास रहने वाले ऐसा मानते हैं कि इस सीवर के आसपास की झुगियों में अधिकतर नकली शराब बनाने वाले, नशे का कारोबार करने वाले और अपराधी लोग रहते हैं। मगर वास्तविकता यह है कि यदि आप अपनी हवेलियों में खड़े होकर उनके बारे में राय बनाने की बजाय इस गड्ढे में झाँककर उन्हें करीब से देखेंगे तो आप भारत के गरीबी से त्रस्त व्यक्ति से मिल पाएँगे। एक मजदूर, ट्रेफ़िक सिग्नल पर वस्तुएँ बेचने वाले या भीख माँगने वाले, वह सब काम करने वाले जो ज़मीन जीने के लिए उन्हें मिलता है, जरूरी लगता है। इसमें से निश्चित रूप से कुछ अपराधी भी होंगे, मगर उनकी संख्या झुगियों से दिखाई देने वाली

बाघों के बहाने वीरान होते गांव

द्वारा निर्देशित यह विस्थापन वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में संरक्षण के नाम पर सबसे बड़ा विस्थापन होगा। ‘बाघ परियोजना’ की शुरूआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके तहत शुरू में देशभर में 9 ‘बाघ अभ्यारण्य’ बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। ‘एनटीसीए’ के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम - 1972’ में संशोधन किया गया। इन्हीं संशोधनों के बाद ‘वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम- 1972’ तथा संशोधित 2006 की धारा 38V(4) (ii) के अंतर्गत प्रत्येक ‘टाइगर रिजर्व’ में ‘बफर क्षेत्र’ अधिसूचित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

‘बफर क्षेत्र’ ‘क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट’ (संकटग्रस्त वन्यजीव आवास क्षेत्र) या ‘कोर क्षेत्र’ के चारों ओर का वह क्षेत्र है, जहां ‘कोर क्षेत्र’ की तुलना में कम प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है एवं ‘क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट’ की समग्रता के लिए आवश्यक है। ‘वन अधिकार क़ानून- 2006’ की कंडिका - 4(2) में प्रावधान है कि संकटग्रस्त बाघ आवासों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श के आधार पर अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी।

इन क्षेत्रों की स्थापना वैज्ञानिक तथ्यों और उद्देश्यों के आधार पर बाघ संरक्षण के उद्देश्य के लिए की जाती है। इन क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जनजातियों या वन-निवासियों के अधिकारों को किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। ‘बफर क्षेत्र’ में लोगों की आजीविका, विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों के साथ वन्यजीव तथा मानवीय कार्यों के सह-अस्तित्व के उद्देश्यों को बढ़ाना जरूरी है। ‘बफर क्षेत्र’ की सीमाओं का निर्धारण वैज्ञानिक तथा उद्देश्यों के आधार पर संबंधित ग्रामसभा और इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श द्वारा होता है।

स्थानीय समुदाय और ‘संरक्षित क्षेत्रों’ (अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान) में वन्यजीवों के बीच टकराव की स्थिति में ‘संरक्षित क्षेत्र’ के अन्तर्गत ‘संकटग्रस्त वन्यजीव आवास क्षेत्र’ घोषित किए जाने की पूरी प्रक्रियाओं के चरण निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत पहले वन अधिकारों की संपूर्ण मान्यता दी जाती है। उचित प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञ समिति गठित की जाती है

त्वंग्य
कारुलाल जमड़ा ‘कारुण्य’

लेखक साहित्यकार हैं ।

बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखकर छत्र को बड़ी हैरानी हुई। वह केवल अंग्रेजी विषय में एक नंबर से विषय योग्यता प्राप्त करने से रह गया था। जहां उसे सारे विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त हुए थे,वहीं केवल अंग्रेजी में एक अंक से कैसे पीछे रह गया ? यह सोचकर उसने अपनी कापी दोबारा चेक कराये का निश्चय किया और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर दिया। कुछ समय बाद उसे अपनी उत्तर पुस्तिका देखने हेतु आमंत्रित किया गया ।जैसे ही उसने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया, वह भीचक्का रह गया।उसने देखा कि एक प्रश्न के सही उत्तर पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया गया था। उसने मूल्यांकनकर्ता मास्टर जी से शिकायत की कि ‘पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है’, इस वाक्य के अनुवाद में उसे एक अंक क्यों नहीं दिया गया जबकि उसने सही किया था। दरअसल उसने उत्तर में लिखा था ‘द अर्थ मूक्स अराउंड द अर्थ’ और अंग्रेजी के मूल्यांकनकर्ता मास्टरजी ने बाद वाले

किसी भी सीवर को अभयारण्य नहीं होना चाहिए

बड़ी इमारतों में रहने वाले सफेदपोश अपराधियों से कम ही होगी।

ये परिवार यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ से उन्हें पुलिस, भू माफिया, शहर स्वच्छता समिति के वाशिदे आदि कोई भगा नहीं सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। पुल के नीचे, रेलवे लाइन के पास, फुटपाथ या अन्य किसी जगह बने ये सीवर उनके लिए अभयारण्य हैं। बाकी स्थानों पर चाहे वे पुल के नीचे



हो, रेल पटरी के पास हो, फुटपाथ पर हो या और कहाँ, कोई न कोई उन्हें वहाँ से हटाने की ताक में लगा रहता है, चूँकि शहरों की जमीन सोने की तरह कीमती है। पर ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि गाँव में उनके घरों में भूख मिटाने के लिए एक समय का भोजन जुटाना भी उनके लिए संभव नहीं हुआ...

हमारी सबसे पवित्र नदी का विस्तार भय है। यह विस्तार उस ऊंचे राजमार्ग से दिखाई देता है। इसका पानी उस सीवर जैसा गंदा और बकबूदार नहीं है लेकिन श्रद्धालु जब इसमें स्नान करते हैं तो अपने रूप को बीमारी में बदल देते हैं।

देश के एक पवित्र तीर्थस्थल पर एक हजार

किलोमीटर ऊपर से आता पानी साफ है मगर इसके किनारे साफ नहीं हैं। एक अन्य चमचमाते राजमार्ग से हम कीचड़ से सने हुए किनारों पर प्लास्टिक-धातु-लकड़ी से बनी जानी-पहचानी झुगियाँ देख सकते हैं। गरीबी ने इन गाँवों के निवासियों को उनके गाँवों से भगा दिया, लेकिन कोई भी उन्हें इन कीचड़ भरे किनारों से नहीं भगाता, जब तक कि वे हर बार बड़े या छोटे मेले के आयोजन पर इन्हें स्वेच्छे से खाली

नहीं कर देते। आसपास के क्षेत्र में धर्म-प्रधान निर्माण कार्य में तेजी से उन्हें कुछ दिहाड़ी काम मिल जाता है या कम से कम उनके पास पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आने वाले हजारों लोगों से मिलने वाली भिक्षा का सुरक्षा कवच ही मिल जाता है। यहाँ के बच्चे चाहे वे सीवर के पास रहते हो या मैले किनारों के पास, वे स्कूल नहीं जाते। पहले तो उन्हें स्कूल में दाखिला ही नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो अत्यधिक व्यस्त रेल पटरी या हाईवे को पार करना बेहद जोखिम का काम है। अधिकतर परिवारों के पास राशन-कार्ड नहीं हैं- जिसका मतलब है कि अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक

देश की संक्षिप्त राजनीतिक समीक्षा

दृष्टिकोण
ध्रुव शुक्ल
लेखक साहित्यकार हैं ।

भारत का एक नागरिक जो आजादी के पाँच साल बाद पैदा हुआ, अपने देश के राजनीतिक परिदृश्य का एक शब्द चित्र बनाता हूँ और पाता हूँ कि मेरे बचपन के दिनों में कॉंग्रेस एक भरी-पूरी गम् गंजाई की तरह थी और जिसे ओढ़कर देश की सभी बिरादरियों के लोग गर्माहट महसूस करते थे। मेरी तरह कई लोग इस गर्माहट को आज भी भूले नहीं हैं। उस समय देश में समाजवादी और प्रजा समाजवादी नाम के दल भी बनें। एक जनसंघ नाम का अल्पज्ञात दल भी था।

गैर कॉंग्रेसवाद का नारा सबसे पहले इन्हीं समाजवादी दलों ने लगाया और इनके पड़े-लिखे नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि वे कॉंग्रेस को हटाने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। इन्हीं ने जनसंघियों से मिलकर संविद सरकार बनाने का राजनीतिक खेल भी खेला। देश को सद्भावपूर्ण राष्ट्रियता का सबक सिखाने वाली कॉंग्रेस की भरी रंजाई से ही रुई नौच-नौचकर कई तरह के जातिवादी दल अपने गद्दे-तकिए भरवाने लगे थे और इंदिरा जी के राजनीतिक समय में खुद कॉंग्रेस भी अपनी भरी-पूरी रंजाई के दो टुकड़े कर चुकी थी। बाद में तो वह कई तुण-मूलों में बिखरती चली गयी।

जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कॉंग्रेस के खिलाफ बिहार आंदोलन प्रारंभ हुआ और उनके आह्वानों से यह संदेह होने लगा कि कहीं देश में अराजकता न फैल जाये। तब इसी कारण देश में आपातकाल लगाने की नौबत भी आयी। जब उन्नीस महीने के बाद आपातकाल हटया गया तो भाति-भाति के जातिवादी, कौमपरस्त, साम्प्रदायिक दल एक ‘जनता पार्टी’ नामक तात्कालिक गठबंधन बनाकर देश की सत्ता पर काबिज हो गये। बाहर से सही पर सायबवादी वामपंथियों ने भी उनका समर्थन किया। वे मात्र ढाई साल में विफल होकर देश के लोगों की नजरों से गिर भी गये। जनता ने फिर कॉंग्रेस को चुना। जब आतंककारी ताकतें इंदिरा जी के प्राण भी ले चुकीं, तब भी राजीव गांधी के नेतृत्व में कॉंग्रेस आगे बढ़ती रही। फिर राजीव जी के प्राण भी ले लिए गये।

यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि जनता के जात-पात में बंटे रहने के कारण और उसकी क्षेत्रीय पीड़ाओं के नाम पर वोटे बंटने वाले छोटे राजनीतिक दल बड़ी तादाद में

उनकी पहुँच असंभव है। अधिकांश के पास भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुँचने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। पीने के लिए पानी जुटाना एक दैनिक संघर्ष है और इस पानी को हासिल करने में उनकी कमाई या काम के घंटे या दोनों खत्म हो जाते हैं। मंदिरों में जाना वर्जित है। बच्चों की पैदाइश में परेशानी होती है चूँकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुँच नहीं है और निजी अस्पतालों में प्रसव अकल्पनीय रूप से पहुँच से बाहर है। मृत्यु अंतिम संस्कार की गरिमा की मांग करती है, जो पीछे जीवित बचे लोगों को और गरीबी में धकेल जाती है।

इस तीर्थ स्थल से दक्षिण में 2000 कि.मी. दूर शहरी कचरे से बना ऐसा ही सीवर और उसके किनारे कतारों में बनी झुगियाँ नजर आएँगीं। यह एक और मध्यम आकार का शहर है, जहाँ गाँवों की तुलना में आजीविका के साधन कम ही है फिर भी यहाँ जीने के लिए साधन उपलब्ध होंगे, यह विश्वास रहता है। यही कारण है कि शहरों में हर तरफ इस तरह की झुगियाँ दिखाई देती हैं।

जो कभी हमारे बड़े शहरों में घटता था, वह अब अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के शहरी केंद्रों में फैल गया है। लेकिन ये केवल झुगी-झोपड़ियाँ नहीं हैं, उनसे भी निम्न स्तर की झुगी-झोपड़ियाँ हैं जो जीवन जीने के सिद्धांत का खंडन करती हैं, उन्हें गहरी खाई में धकेलती है। अगर हम पर्याप्त नौकरियों और आजीविका के अवसर नहीं बनाते हैं और यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि वे पूरे भारत में समान रूप से वितरित हो तो मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। एक राष्ट्र के रूप में बल्विक वैश्विक स्तर पर भी यह स्पष्ट है कि हम ऐसा करना नहीं जानते, मगर यह स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है कि हम नहीं जानते हैं तभी अनुसंधान और नीति से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने और व्यवसाय तक हर आयाम पर आवश्यक सहन प्रयासों की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बीच हम अपने सबसे गरीब लोगों के लिए संसाधन बुनियादी चीजें सुलभ नहीं करवा सकते। अगर हमारी कारों के लिए हाई-स्पीड हाईवे बनाए जा सकते हैं तो उनके पास भोजन, पानी, बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे पास इन्हीं से अधिकांश के लिए कल्याणकारी योजनाएँ हैं लेकिन इन झुगी-झोपड़ियों के निवासियों की उन योजनाओं तक पहुँच लगभग नहीं के बराबर है। हमें इसे दृश्य को बदलना होगा। देश में कहीं भी किसी भी सीवर को नागरिकों के लिए अभ्यारण्य नहीं होना चाहिए।

देश की संक्षिप्त राजनीतिक समीक्षा

खड़े होकर कॉंग्रेस की सर्वसमावेशी शक्ति को कमजोर करने लगे थे और इन दलों ने ही कॉंग्रेस को सत्ता के स्वार्थी गठबंधनों की तरफ दबाव बनाकर खींचा। जो कॉंग्रेस देश के दिल को जीतकर शासन चलाती थी, उसे इन वोट के खुदरा व्यापारियों के दलों के दलदल में फँसना पड़ा। सोनिया गांधी को इन गठबंधनों के मेंढकों को तौलने में अपना समय गँवाना पड़ा।

भारतीय जनता पार्टी ने इन राजनीतिक गुम्टियों के नेताओं को पहले साथ लेकर और फिर इनका भेद जानकर वोट के इस खुदरा व्यापार में संधें लगायी तो ये दल उसके खेत में खिसकने लगे। सबसे पहले इन मेंढकों को अटल बिहारी वाजपेयी ने पाँच साल तक किसी तरह तौला। ये दल यहाँ कहते पाये गये हैं कि कॉंग्रेस और भाजपा तो एक जैसे ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता पाने के लिए दोनों में अपनी जगह बनायी जा सकती है। इन खुदरा दलों की घुसपैठ के कारण इतना बड़ा देश करीब आधी सदी से ‘कामन मिनिमम प्रोग्राम’ से ही चल रहा है। वह अपनी समृद्धि का कोई बड़ा सपना देख नहीं पा रहा। मैंने अभी तक वोट के इन खुदरा व्यापारी नेताओं को देश की अर्थनीति, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर कोई गंभीर विमर्श करते हुए नहीं सुना। वे केवल वोट बंटोरने के लिए जातियों का नाम स्मरण ही करते रहते हैं। ये उन्हें गोर गिन्ते रहते हैं कि कहीं उनके लिए कम न पड़े जाये।

इन दलों के राजनीतिक हथकण्डे अब किसी से छिपे नहीं हैं। उनके मन में बस यही विचार चलता रहता है कि इन दो राष्ट्रीय दलों...कॉंग्रेस और भाजपा...के दो पाटों के बीच उनका क्या होगा। ये वह भी जानते हैं कि भाजपा की नयी रंजाई में बहुत सारी रुई तो कॉंग्रेस की रंजाई से ही नौचकर भरी गयी है। उसमें अब महात्मा गांधी के द्वारा धुनका हुआ कपास नहीं रह गया है। भाजपा ने इस रंजाई में अग्राहित बी टी काटपत्र भी खुब भर लिया है। देश में विकसित हो रही हिन्दू राजनीति देश को माटी में उगे उस कपास के फूल को भूतनीं जा रही है जिसकी उज्ज्वलता को संत हृदय के समान माना गया है।

आजादी के पचहत्तर साल बीत गये और देश के कपास के फूलों पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद की राजनीतिक मूल जमती चली गयी। गांधी जी की तरह अब वे लोकतंत्र के जुलाहे और बुनकर नेता कहीं रहे तो इस मैली रुई को धुनकर लोकतंत्र को टण्ड में ठिठुरने से बचाने के लिए नयी रंजाई भर सकें। उसे इस तरह ताक सके कि बिना किसी भेदभाव के पूरा देश उसे फिर ओढ़ सके।

सबसे महत्वपूर्ण विभाग ‘रेवेन्यू’। इसका तात्पर्य ही है अर्थ प्राप्त करना और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र अर्थ के लिए ही तो काम कर रहा है।पूरी दुनिया ‘राजस्व’ से अर्थात् ‘अर्थ’ से जुड़े हुए लोगों को ही सलाम करती है। आप स्वयं देखिए सरस्वती की साधना करने वाले शिक्षक गौण है उन लोगों के समक्ष जो कि निरंतर धन के लिए यानि ‘अर्थ’ के लिए प्रयासरत रहते हैं। इन सब विस्थितियों में देखा जाए तो हर व्यक्ति पैसे के पीछे ही भागता नजर आ रहा है। सही है ना सर? अरे ! व्यक्ति ही क्या सम्पूर्ण पृथ्वी ही धन याने ‘अर्थ’ के पीछे भागती है अर्थ के लिए। अब मैंने ‘द अर्थ मूक्स अराउंड द अर्थ’ लिख दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया ?

मास्टर जी सरस्वती के उपासक होते हुए भी यह भलीभांति जानते थे कि उनके आसपास का हर हाथ,हर पैर, हर माईड, यहां तक कि सम्पूर्ण परिवेश ‘अर्थ’ के पीछे भाग रहा था। उन्हें स्वयं भी कई बार ब्याज में पैसे उधार लेने पड़ते थे क्योंकि उनका माईड इस अर्थ की महत्ता को समझ नहीं पाया था।वे छत्र के अकाट्य और विशुद्ध व्यवहारिक तथ्यों को काट नहीं पाये। उन्हें लगने लगा कि विद्या अर्जन का अर्थमय उद्देश्य अर्थोपार्जन ही तो है। हाक्कट उन्होंने मान लिया कि वास्तव में आजकल अर्थ याने ‘पृथ्वी’ सूर्य की जगह ‘अर्थ’ याने धन के आसपास ही घूम रही है और वह स्वयं इस बात का अर्थ भले ही न जाने पाए हों,या इसे सही नहीं मानते हों परंतु वर्तमान जनरेसन इस तथ्य का अर्थ भलीभांति समझ रही थी। ‘अर्थ’ का महत्व समझने का अर्थ। समय के साथ चलने का अर्थ।



मुद्दा

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।



मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा 3 मई, 2023 को भड़क उठी। इस संघर्ष में 200 से अधिक मौतें हुईं और 60,000 लोग विस्थापित हुए। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष की जड़ें मणिपुर के जातीय और ऐतिहासिक संदर्भ में गहराई से जुड़ी हुई हैं। मुख्य रूप से घाटी क्षेत्रों में रहने वाले मेइतेई और पहाड़ी जिलों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से सामाजिक-राजनीतिक और भूमि सम्बंधी विवाद हैं। राजनीतिक सत्ता, भूमि और सरकारी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा ने इन समुदायों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। आरक्षण, भूमि स्वामित्व और स्वायत्तता से सम्बंधित नीतियाँ इस टकराव के केंद्र में हैं। आदिवासी और गैर-आदिवासी समूहों को वर्गीकृत करने की ब्रिटिश काल की नीतियों ने विभाजन पैदा किया जो आज भी गूजता है।

कानून-व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ गई, सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसक घटनाएँ सामने आईं। सांप्रदायिक विभाजन ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) अधिकारियों के कामकाज को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उनके बीच भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएँ पैदा हुईं, संघर्ष के कारण पहाड़ी और घाटी जिले दुर्गम हो गए। वर्तमान स्थिति सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा परिकल्पित 'स्टील फ्रेम' के लिए खतरा है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएँ भारत की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ हैं। हिंसा और जातीय विभाजन के कारण एंस्टर डे कॉर्पस (अधिकारियों के बीच एकता और आपसी सम्मान) तनाव में हैं, जिससे अधिकारियों के बीच सहयोग और विश्वास कमजोर हो रहा है। संघर्ष ने एआईएस अधिकारियों के बीच पारस्परिक सम्बंधों पर गहरा प्रभाव डाला है, सामाजिक आदान-प्रदान और सहयोग दुर्लभ हो गए हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण, प्रचार और ऑनलाइन

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर ने एक बार फिर से समाज की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेन्नई के एक अस्पताल में एक महिला को सिर्फ इसलिए पैप स्मीयर टेस्ट से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह अविवाहित थी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज अभी भी महिलाओं के स्वास्थ्य को सेक्स और विवाह जैसे मुद्दों से जोड़कर देखता है। एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिकल एनालिस्ट के रूप में, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह की सोच न सिर्फ महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी खतरे में डालती है।

हमारा समाज आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर पुराने और बेबुनियादी धारणाओं में उलझा हुआ है। जब एक अविवाहित महिला को ज़रूरी चिकित्सा सेवाओं से वंचित किया जाता है, तो यह एक तरह से उसे उसकी व्यक्तिगत पहचान और स्वास्थ्य के लिए योग्य न मानने जैसा है। यह सोच महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है, जिसमें उन्हें अपराधबोध, शर्मिंदगी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल उनकी यौनिकता या विवाहिक स्थिति से जोड़ना न सिर्फ तर्कहीन है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ता है। ऐसी घटनाएँ महिलाओं में आत्म-संदेह और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।

समाज में अभी भी यह धारणा बनी हुई है कि

सियान समिट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ग्यारहवीं बार भाग लिए, 10 वर्ष पहले उन्होंने भारत के 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी की घोषणा की थी, तो बहुत चर्चा हुई थी। अब एक दशक बीत चुका है। इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊँचाई, दिशा और गति दी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इस महासम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि 21वीं सदी एशियाई सदी भारत और आसियान की सदी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आसियान देशों के बीच एक बड़ी समस्या यह है कि देश मतभेद और मनभेद के साथ आगे बढ़ रहे हैं जाहिर भले न करें। ईस्ट एशिया पॉलिसीज पर यदि काम हुआ होता, सभी देश मिलकर अपने आपसी तनाव को दूर करते तो शायद ईस्ट एशिया में समन्वय व सामंजस्य की स्थितियाँ कुछ और होती। यद्यपि इन सबके बीच भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सकारात्मक भाव से अपनी बात कहने से नहीं चूके। उन्होंने अपने समायन वक्तव्य में सबके सामने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमने जो दो संयुक्त वक्तव्य अपनाया है, वे आने वाले समय में हमारे सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आपके सहयोग से भारत और आसियान संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

आसियान का नया संयोजक देश फिलीपींस बना है। अब अगली बार फिलीपींस में आसियान के लोग इकट्ठा होंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास जताया कि मुझे विश्वास है कि हम मिलकर दो बिलियन लोगों के

मणिपुर की जातीय हिंसा, अधिकारियों की अग्नि परीक्षा



और ऑफलाइन दोनों तरह से सार्वजनिक चर्चा के ध्रुवीकरण ने रिशतों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के अधिकारियों के लिए एक साथ काम करना मुश्किल हो गया है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध, दुष्प्रचार और आर्थिक व्यवधान जैसे गैर-गतिशील तत्वों ने मणिपुर में तनाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाइब्रिड युद्ध के हिस्से के रूप में इन युक्तियों ने जनता के मनोबल और शासन में विश्वास को कम कर दिया है, जिससे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार आईएसएस और अन्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा हो गई है। विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के सिविल सेवकों को अपनी जातीय पहचान के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को संतुलित

करने में दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सामुदायिक अपेक्षाओं और वफादारी का दबाव बनाम प्रशासनिक तटस्थता बनाए रखने की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। कई अधिकारियों को उनकी जातीयता के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों को भीड़ द्वारा निशाना बनाए जाने और सुरक्षा की आवश्यकता की रिपोर्टें उनके सामने आने वाले गंभीर खतरों को रेखांकित करती हैं। इससे मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा हो गया है और उनके कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।

दुष्प्रचार, घृणास्पद भाषण और भड़काऊ सामग्री फैलाने में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की भूमिका ने संघर्ष को बढ़ा दिया है। हिंसा और भड़काऊ भाषणों के

वीडियो ने समुदायों को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है, जिससे नागरिक अधिकारियों के लिए कहानी को प्रबंधित करना मुश्किल हो गया है। चुनौतियों के बावजूद, मणिपुर संघर्ष को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) जैसे संस्थानों द्वारा अनुसंधान और दस्तावेजीकरण के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। इस मामले के आधार पर संघर्ष प्रबंधन, सुलह और प्रशासनिक तटस्थता पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और क्षमता-निर्माण कार्यशालाएँ विकसित की जा सकती हैं। इस तरह के केस अध्ययन लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जातीय केंद्रित संघर्षों से निपटने में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे, जो संघर्ष

क्षेत्रों में शासन की शैक्षणिक और व्यावहारिक समझ में योगदान देंगे।

वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की अवैयक्तिक प्रकृति का लाभ संघर्षग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किया जा सकता है। बैचमेट्स के बीच पेशेवर टीम भावना और राष्ट्रीय एकीकरण के एजेंट के रूप में एआईएस अधिकारियों की तटस्थ भूमिका संघर्षों को हल करने के लिए एक लचीला ढांचा प्रदान करती है। शांति-निर्माण प्रयासों में अधिकारियों को शामिल करने के लिए नवीन कार्मिक प्रबंधन नीतियों का कार्यान्वयन। विभिन्न जातीय समुदायों के अधिकारियों के बीच नियमित आभासी बैठकें बेहतर सम्बंधों को बढ़ावा दे सकती हैं और संघर्ष से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक अलगाव को कम कर सकती हैं। इस तरह के उपाय मणिपुर में उभरे प्रशासनिक सिलोस को तोड़ने में मदद कर सकते हैं, सिविल सेवाओं के भीतर बेहतर सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और शांति प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। यह संघर्ष भारत में संघीय एकता के महत्व को भी रेखांकित करता है। संचार चैनलों को मजबूत करने और राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने से भविष्य के संघर्षों को कम करने में मदद मिल सकती है।

मणिपुर में जातीय हिंसा ने गहरे जड़ें जमा चुके सांप्रदायिक संघर्षों से निपटने में भारत की प्रशासनिक प्रणाली की कमजोरी को उजागर कर दिया है। हालाँकि यह स्थिति अखिल भारतीय सेवाओं की अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, यह संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में शासन के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार और सुधार करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करती है। क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नवीन नीति उपायों पर ध्यान केंद्रित करके, आईएसएस और अन्य सेवाएँ संकट को एक सीखने के अनुभव में बदल सकती हैं जो भविष्य के संघर्षों में 'स्टील फ्रेम' के लचीलेपन को मजबूत करती है।

संकेत

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ



हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर ने एक बार फिर से समाज की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेन्नई के एक अस्पताल में एक महिला को सिर्फ इसलिए पैप स्मीयर टेस्ट से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह अविवाहित थी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज अभी भी महिलाओं के स्वास्थ्य को सेक्स और विवाह जैसे मुद्दों से जोड़कर देखता है। एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिकल एनालिस्ट के रूप में, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह की सोच न सिर्फ महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी खतरे में डालती है।

हमारा समाज आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर पुराने और बेबुनियादी धारणाओं में उलझा हुआ है। जब एक अविवाहित महिला को ज़रूरी चिकित्सा सेवाओं से वंचित किया जाता है, तो यह एक तरह से उसे उसकी व्यक्तिगत पहचान और स्वास्थ्य के लिए योग्य न मानने जैसा है। यह सोच महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है, जिसमें उन्हें अपराधबोध, शर्मिंदगी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल उनकी यौनिकता या विवाहिक स्थिति से जोड़ना न सिर्फ तर्कहीन है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ता है। ऐसी घटनाएँ महिलाओं में आत्म-संदेह और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।

समाज में अभी भी यह धारणा बनी हुई है कि



देखना एक गंभीर समस्या है। इससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है और यह उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाता है।

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये का गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें लगाता यह महसूस कराया जाता है कि उनका स्वास्थ्य उनके विवाहिक या यौनिक संबंधों पर निर्भर है। यह सोच उन्हें चिंता, अवसाद और मानसिक दबाव में डाल सकती है, जो

उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है।

एक मनोचिकित्सक के रूप में मेरा मानना ​​है कि समाज को इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। महिलाओं के स्वास्थ्य को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उन्हें बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए। यह सिर्फ उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है।

इस तरह के भेदभावपूर्ण रवैये को रोकने के लिए हमें महिलाओं के प्रति समाज की सोच को बदलना होगा। उन्हें उनके स्वास्थ्य के मुद्दों पर जज करना गलत है। समाज में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का एक बड़ा कारण यही मानसिकता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं का स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है और इसमें कोई भी पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं होना चाहिए।

समाज को महिलाओं के स्वास्थ्य को सेक्स और विवाह जैसे मुद्दों से ऊपर उठकर देखना होगा। यह सिर्फ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को उनकी चिकित्सा ज़रूरतों के आधार पर सम्मान मिले, न कि उनकी विवाहिक या यौनिक स्थिति के आधार पर। एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में, मेरा मानना ​​है कि इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने और ठोस कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है, ताकि महिलाओं को समाज में बिना किसी भेदभाव के उनका हक मिल सके।

विश्व राजनीति

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रीय के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में वेयर प्रोफेसर हैं।



आसियान समिट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ग्यारहवीं बार भाग लिए, 10 वर्ष पहले उन्होंने भारत के 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी की घोषणा की थी, तो बहुत चर्चा हुई थी। अब एक दशक बीत चुका है। इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊँचाई, दिशा और गति दी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इस महासम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि 21वीं सदी एशियाई सदी भारत और आसियान की सदी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आसियान देशों के बीच एक बड़ी समस्या यह है कि देश मतभेद और मनभेद के साथ आगे बढ़ रहे हैं जाहिर भले न करें। ईस्ट एशिया पॉलिसीज पर यदि काम हुआ होता, सभी देश मिलकर अपने आपसी तनाव को दूर करते तो शायद ईस्ट एशिया में समन्वय व सामंजस्य की स्थितियाँ कुछ और होती। यद्यपि इन सबके बीच भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सकारात्मक भाव से अपनी बात कहने से नहीं चूके। उन्होंने अपने समायन वक्तव्य में सबके सामने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमने जो दो संयुक्त वक्तव्य अपनाया है, वे आने वाले समय में हमारे सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आपके सहयोग से भारत और आसियान संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

आसियान का नया संयोजक देश फिलीपींस बना है। अब अगली बार फिलीपींस में आसियान के लोग इकट्ठा होंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास जताया कि मुझे विश्वास है कि हम मिलकर दो बिलियन लोगों के

आसियान समिट में मोदी का दो टूक संदेश

उज्ज्वल भविष्य और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। अब दो बिलियन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। दो बिलियन लोग ज्यादा सुखी नहीं हैं। गरीबी भी यहाँ है, भूखमरी भी है। आपदा प्रबंधन ठीक नहीं है। डिजिटलीकरण की बात हर मंच से हो रही है लेकिन सच यह है कि इन दो बिलियन में कुछ मिलियन ऐसे भी हैं जो अंधेरे में हैं अर्थात उनके यहाँ तक अभी विद्युत नहीं पहुँची है।

आसियान के इस मंच पर इन बड़ी मुश्किलताओं के साथ जिन बातों पर ज्यादा ध्यान देना ज़रूरी है वह है प्रति व्यक्ति आय और न्याय। हम जानते हैं कि मानवाधिकार के बहुत मसलें आसियान देशों में चर्चा के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सबके सामने सकारात्मक बात करना ठीक है लेकिन स्थितियाँ यदि आसियान के सभी सदस्य देश ठीक करेंगे तभी ठीक होंगी।

सात आसियान देशों के साथ सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी भारत की है। तिमोर-लेस्ते में भारत ने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था, जिसके साथ भारत ने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंद विश्वविद्यालय (भारत) में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज शुरू किया गया है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया की साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक



आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक-दूसरे को सहायता दी गयी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें 30 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में लगभग यह सब बातों की है। इसके पीछे मंशा समझिए प्रधान मंत्री

की। वह चाहते हैं कि आसियान विश्व में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। सबमें साझेदारी की भावना शुरू हो। सभी आसियान देश एक-दूसरे के साथ सहयोग के लिए एक-दूसरे को जोड़ने वाली मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करना ज़रूरी बात यह है कि आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक चाहता है। डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत फंड बनाया है तो डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी के लिए भी भारत पहले से ही प्रतिबद्ध है। ज्ञान भागीदारी, वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को बहुपक्षीय सहयोग भी करने के लिए भारत आह्वान कर चुका है। मिशन लाइफ पर मिलकर काम करने, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाएँ उपलब्ध कराने, आतंकवाद,

आतंकी वित्तपोषण और साइबर-दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ने, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने और आपदा प्रबंधन में सहयोग करने, समुद्री हिफाजत, सुरक्षा और क्षेत्रीय जागरूकता पर अधिक सहयोग करने और समुद्री सहयोग व खाद्य सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता वाला देश भारत यह चाहता है कि आसियान पूर्वी एशिया के लिए मद्दमाग साबित हो और वैश्विक स्तर पर भारत को साथ लेकर चले और विश्व का कल्याण करे।

यह एक विशिष्ट पहल भारत की ओर से जो आसियान के बारे में की जा रही वह ऐतिहासिक है और निश्चय ही भारतीय जनमानस के गरिमा के अनुकूल भी है। आसियान देशों की ओर से यदि ऐसे सहयोग मिले जिससे भारत आसियान के हर एक व्यवस्था में अहम् भूमिका निभाते हुए एक गतिशील विश्व व्यवस्था कायम करने में सहयोगी साबित होगा तो निश्चय ही यह भारत के लिए और विश्व के लिए अच्छी बात होगी। बड़े व्यापक पैमाने पर इसलिए आसियान के मसले को समाप्त करने की आवश्यकता है और यह कोशिश करनी होगी कि आसियान के देशों में विवाद के मसले हैं और जो चुनौतियाँ हैं, उसे यथाशीघ्र समझ लिया जाए और विश्व को एक नई दिशा दी जाए।

साड़ी रणनीतियाँ जो इस वर्ष आसियान के मंच से संज्ञान में लायी गयी हैं वे किसी भी दशा में पूरी करने की कोशिश हो और न्यायपूर्ण विश्व के विकास के लिए प्रयास किए जाएँ। दुनिया के हितों को ध्यान में देने की आवश्यकता है और यह भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व किन चुनौतियों की ओर बढ़ रहा है और आसियान देश इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कोशिश कर सकते हैं। भारत की ओर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और साझेदारी की पूरी पहल की जो कि अभूतपूर्व आसियान निर्माण के लिए है। यदि सभी इसको समझकर आगे बढ़ेंगे तो सपूर्ण आसियान देशों के हित में होगा।



खाद्य विभाग ने लिए 14 सैपल

बैतूल। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों से सैपल लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत



अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने टीम के साथ प्रभातपट्टन एवं शाहपुर में स्थित होटल तथा दुकानों का औचक निरीक्षण कर 14 सैपल लिए। इस दौरान प्रतिष्ठानों, दुकानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण में संचालकों को रख-रखाव की समझाइश दी। खाद्य विभाग से शशि भारतीय ने प्रभात पट्टन में नमकीन के 5, मिठाई के 4 इस प्रकार कुल 9 सैपल तथा शाहपुर से मीना कुमरे मिठाई के 2, पनीर के 1, खोवा के 1, बिस्कुट के 1 इस प्रकार कुल 5 सैपल लिए। लिए गए सैपल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

देवर की हत्या करवाने वाली मामी गिरफ्तार

बैतूल। मामूली झगड़े पर देवर की हत्या करवाने वाली महिला को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने अप्रैल 2024 में देवर की हत्या करवाकर उसका शव जलवा दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं उक्त महिला फरार थी। जिसने दो लोगों को महज दो हजार रुपए में अपने देवर की हत्याके लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया कि 27 अप्रैल को कोतवाली थाना के मलियाढाना में किसान श्यामा उर्दके के खेत की बंधिया के नीचे एक शव जला हुआ मिला था। मामले में मृतक की शिनाख्त 6 महीने बाद डीएनए परीक्षण के बाद शंकर के रूप में हुई थी। कोतवाली पुलिस ने पांच दिन पहले मामले का खुलासा करते हुए संदीप दहीकर निवासी बरां कास्या, थाना झल्लार और नीलेश चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की मुख्य आरोपी और पूरी साजिश रचने वाले मनीता दहीकर फरार थी। जिसे पुलिस ने ताप्ती नदी के पास दादूढाना में गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में टीआई देवकरण डेहरिया ने बताया कि मामले में एसआई राकेश सरैयाम, चित्रा कुमरे, ब्रिजेश खुर्वशी, निर्मला, लीमा मरकाम एवं साइबर सेल की टीम की विशेष भूमिका रही।

दृष्टिबाधित-दिव्यांग बच्चों की प्रदर्शनी कल

न्यू बैतूल स्कूल में बच्चे की होगी कार्यशाला

बैतूल। न्यू बैतूल हाईस्कूल प्रबंधन समिति के सचिव मोहित गर्ग ने बताया कि दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित बच्चों के द्वारा बनाई गई दीयों की प्रदर्शनी का आयोजन कल कोतवाली थाने के पीछे



स्थित न्यू बैतूल स्कूल कोठीबाजार में किया जाएगा। श्री गर्ग ने बच्चों की कला को प्रोत्साहित करने और उसका उत्पावर्धन करने की लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों द्वारा बनाई गई इन कलाकृतियों को क्रय कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गौरतलब हो कि जय नारायण सर्वोदय विद्यालय समिति धरौदा केन्द्र करजगांव के दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों ने अपने हाथों से दीपावली के लिए सुन्दर दीपक एवं रंगोली निर्मित की है। बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को क्रय कर दिव्यांग बच्चों के जीवन को रोशन करने की सभी से अपील की गई है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने चलाया प्रशिक्षण बांस और शिल्प निर्माण सीख रही महिलाएं

बैतूल। राष्ट्र को विकसित बनाना है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी तारतम्य में सेंट्रल बैंक की संस्था आरसेटी द्वारा भारत भारती में प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। इस मौके पर



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होशंगाबाद महाप्रबंधक रजत मिश्रा का आरसेटी में आगमन हुआ। जिसमें आरसेटी में चल रहे बांस एवं शिल्प निर्माण प्रशिक्षण की 25 महिला प्रशिक्षणार्थियों को उत्साहवर्धित किया एवं प्रतिभागियों को आगे बढ़ने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया एवं बीसी सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम में उपस्थिति हुई। जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एके सिंह, सीनियर मैनेजर सौरभ कुमार, आरसेटी निदेशक मंजूषा आठवले एवं आरसेटी का समस्त स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

बैतूल विधायक ने शाहपुर के एकलव्य विद्यालय पहुंचकर ली मामले की जानकारी

एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को लगाई जमकर फटकार

संजय द्विवेदी बैतूल। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने का मामला सामने आया था। आरोप था कि संस्था के प्रमुख ने जब सीसीटीवी कैमरे का मामला सामने आया, तो हार्ड डिस्क तोड़ दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उर्दके और अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर मामले की विस्तार से जानकारी हासिल की। संस्था प्रमुख से मामले के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। गौरतलब रहे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के आरोप लगे थे। यह भी आरोप था कि पंकज सरन और इसके साथियों ने नाबालिक छात्राओं के विरोध के बाद सबूतों को मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर की दोनों हार्ड ड्राइव को नष्ट करने तोड़ दी। परंतु जब यह सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास पहुंची, तब इसको लेकर मामला गरमा गया और यह शर्मनाक घटना बाहर आई। स्थानीय भाजपा नेता अमित महतो द्वारा इस जघन्य कार्य को लेकर संस्था प्राचार्य से चर्चा की गई।

विधायक ने जताई नाराजगी- इस मामले को लेकर विधायक एकलव्य आवासीय विद्यालय पहुंची।



उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद प्राचार्य पंकज शारण को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया, लेकिन विधायक होने के नाते उन्हें सूचित तक नहीं किया गया। उन्होंने प्रबंधक से सवाल किए कि जब चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो छात्राओं को यहां कैसे रूकवाया? उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी हो सकती है। सीडीआर नष्ट करने से सारी जानकारीयां दफन हो गईं। इसके बाद विधायक ने प्राचार्य, क्षेत्र के बीआरसी और बीईओ के साथ आधे घंटे चर्चा कर मामले की जानकारी हासिल की। पूरे समय विधायक के तेवर तीखे होने से अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा।

इनका कहना है -

सीडीआर नष्ट करने के मामले में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। विधायक ने महिला एसआई को बुलाया जरूर था, लेकिन इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए हैं।

- मयंक तिवारी,
एसडीओपी, शाहपुर

हर घर दिवाली अभियान में प्रत्याशा आनंद वलब बनेंगे सहयोगी

बैतूल। प्रत्याशा आनंद क्लब बैतूल एवं द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंद संस्थान के आह्वान पर हर घर दिवाली अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रत्याशा आनंद क्लब की अध्यक्ष सुश्री तुलिका पचौरी ने कहा कि राज्य आनंद संस्थान अपने कार्यक्रमों में मदद को प्रोत्साहित करता है, जिसमें अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को दूसरों के प्रयोग के लिए देते हैं। दीपावली का पर्व मदद की अवधारणा को अपनाने का एक बेहतर अवसर प्रदान करता है, इस संदर्भ में हर घर दिवाली अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आनंदको के सहयोग से नगर में लोगों से संपर्क कर उनसे आग्रह किया



जाएगा कि वह अपने शहर से विभिन्न बस्तियों में रहने वाले घरों में भी दिवाली का पर्व अच्छे से मना सके इसके लिए उन्हें अपने घरों या अन्य स्रोत से अतिरिक्त सामग्री प्रदान कर सकें ऐसी वस्तुओं को अपने निकट के आनंद आंगनवाड़ी केंद्र नेकी की दीवार में छोड़ने का नागरिकों एवं संगठनों से अनुरोध किया जा रहा है। जिनके घर में जो भी वस्तुएं ज्यादा है उन वस्तुओं को वह उन लोगों के लिए दे सकते हैं जिनके घर में उन चीजों का अभाव है। दिवाली के अवसर पर साफ सफाई के दौरान बहुत सा सामान हर घर से ऐसा निकलता है जो घरों में आवश्यकता से अधिक होता है, वह ऐसी वस्तुएं जैसे कपड़े, बर्तन, बच्चों के खिलौने, कुर्सी, टेबल, अलमारी, सोफा सेट इत्यादि, यह सामान हम आनंद आंगनवाड़ी केंद्र (विकास वाई केसर बाग के पीछे) में ले जाकर दे सकते हैं ताकि यह वस्तुएं उन लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिन्हें उनकी आवश्यकता है। श्रीमती निमिषा संजय शुक्ला ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप पुरानी वस्तुएं ही दे सकते हैं आप नए कपड़े, स्वेटर, साल, पटाखे, मिठाई, रंगोली, दिये आदि के छोटे-छोटे पैकेट भी बना कर दे सकते हैं।

होम्योपैथिक अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति होम्योपैथिक उपचार के प्रति बढ़ा विश्वास

बैतूल/ भोरा। वर्षों से नगर के शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल में डॉक्टर न होने से यह अस्पताल केवल नाम मात्र का बनकर रह गया था। अधिकतर लोग एलोपैथिक उपचार की ओर झुकाव रखते थे, और होम्योपैथिक चिकित्सा को महत्वहीन समझते हुए इसे कारगर नहीं मानते थे। अस्पताल में सिर्फ एक कंपाउंडर के भरोसे उपचार होने के कारण होम्योपैथिक चिकित्सा का भरोसा भी टूटने लगा था। हाल ही में शासन द्वारा डॉ. कंचन वर्मा की नियुक्ति से स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। डॉ. वर्मा की विशेषज्ञता, उपचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मरीजों के लिए उनके समर्पण ने स्थानीय लोगों में होम्योपैथी के प्रति नया विश्वास जगाया है।



मरीज, जो पहले केवल एलोपैथिक उपचार को ही कारगर मानते थे, अब होम्योपैथिक चिकित्सा को भी आजमा रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। डॉ. कंचन वर्मा ने कहा, होम्योपैथी एक प्रभावशाली और सुरक्षित चिकित्सा प्रणाली है जो न केवल बीमारी के लक्षणों को बल्कि उसकी जड़ को भी उपचारित करती है। मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक इस चिकित्सा का लाभ

पहुंचाना है, ताकि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहें। डॉ. वर्मा के आगमन से अस्पताल की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, और अब लोग नियमित रूप से होम्योपैथिक उपचार के लिए अस्पताल आने लगे हैं। डॉ. कंचन वर्मा की नियुक्ति के बाद से अस्पताल में मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब लोग सिर्फ सामान्य बीमारियों के लिए ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और जटिल रोगों के उपचार के लिए भी होम्योपैथिक चिकित्सा को अपना रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि होम्योपैथिक अस्पताल में इसी प्रकार सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखी जाए, ताकि इस चिकित्सा पद्धति का लाभ निरंतर मिलता रहे।

दिसंबर माह के अंत तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करें

कमिश्नर श्री तिवारी ने मीटिंग में अधिकारियों को दिए निर्देश



बैतूल। बैतूल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त के. जी. तिवारी ने गुरुवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि दिसंबर माह के अंत तक जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करें। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन के अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम के अधिकारी तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी मौजूद थे। संभाग आयुक्त श्री तिवारी ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने का प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करें तथा युद्ध स्तर पर कार्य कर हर परिवार के घर में शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि इस योजना में धनराशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जल जीवन मिशन की प्रगति की प्रतिदिन नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बैतूल जिले के कुल 1338 ग्रामों के 266019 परिवारों में से 220173 परिवारों के घरों में नल से जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस तरह जिले में इस योजना के तहत उपलब्धि कुल 82.77 प्रतिशत है।

प्रस्तुत कर विधिवत अनुमति लें। कमिश्नर श्री तिवारी ने कलेक्टर श्री सूर्यवंशी से कहा कि जिन ग्रामों में पेयजल योजनाओं के अधिक कार्य लंबित हैं वहां अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी मॉनिटरिंग के लिए लगाई जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जाती है, तथा समय-समय पर पेयजल योजनाओं के निरीक्षण के लिए दौरे भी नियमित रूप से किया जा रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर श्री तिवारी को आश्चस्त किया कि जिला प्रशासन की टीम दिसंबर माह के अंत तक दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।

जिलास्तरीय कराते प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दम 14वीं जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जीते गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

बैतूल। जिले में कराते के प्रति जुनून और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए 14वीं जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय गाढ़घाट बैतूल में किया गया। जिला कराते एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी सुनील पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले के 200 से अधिक कराते खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे किया गया, जो शाम 5 बजे तक चला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कराते एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहान राजेंद्र सिंह



तोमर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरीश गढ़ेकर और विशिष्ट अतिथि सिंहान ओमकार महोबे, सेल्फ डिफेंस ऑफ इंडिया कराटे के टेक्निकल डायरेक्टर सिंहान मिसोनकर आर. तारन बैतूल

जिला सचिव सिंहान रमेश धुर्वे, कोषाध्यक्ष सियाराम वट्टी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कराते जिला कोच महेंद्र सोनकर ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य विक्रम सिंह राजपूत ने की।

भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत मिले लक्ष्य को नरसिंहपुर विधानसभा ने किया पूर्ण कैबिनेट मंत्री नरसिंहपुर विधायक प्रह्लाद सिंह पटेल ने कार्यकर्ता को दी शुभकामनाएं

नरसिंहपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यता अभियान के तहत नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। क्षेत्र में 100 प्रतिशत सदस्यता का लक्ष्य पूरा किया गया है, जिसे पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस अभियान के सफल समापन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच उत्साह देखा जा रहा है।कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा के विधायक प्रह्लाद सिंह पटेल ने इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उनके



समर्पण की सराहना की उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान केवल संख्या बढ़ाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह पार्टी के मूल्यों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है प्रह्लाद पटेल ने कहा कि यह उपलब्धि कार्यकर्ताओं की मेहनत, टीम वर्क और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है उन्होंने आगे कहा कि नरसिंहपुर की जनता का भाजपा पर विश्वास और समर्थन इस सदस्यता अभियान की सफलता का मुख्य कारण है भाजपा के इस सदस्यता अभियान का उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना और पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है पार्टी ने पूरे राज्य में इस अभियान को जोर-शोर से चलाया है, और नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त लक्ष्य का 100व सदस्यता हासिल होना इस बात का संकेत है कि पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है भाजपा के स्थानीय नेतृत्व ने भी इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने कहा कि नरसिंहपुर विधानसभा में इस तरह की उपलब्धि पहली बार देखी गई है, जो आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सफलता केवल शुरुआत है, और पार्टी भविष्य में और भी मजबूत होकर उभरेगी। इस प्रकार, भाजपा का सदस्यता अभियान नरसिंहपुर विधानसभा में न केवल संगठनात्मक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक रूप से भी पार्टी को और अधिक सशक्त करेगा उक्त जानकारी विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा दी।

शिक्षा विभाग की बैठक में हुई विस्तृत समीक्षा कलेक्टर ने छात्रावासों में सौ फीसदी प्रवेश करवाने के दिये निर्देश

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे- सीडब्ल्यूएसएन, ड्रॉप बॉक्स, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे- एनएएस, एमपी टास्क छात्रवृत्ति आदि के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्टर ने समस्त संकुल प्राचार्य तथा बीईओ व बीआरसी को निर्देशित किया कि वे 10 नवम्बर 2024 तक कक्षा पहली में टर्ज सभी विद्यार्थियों के आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र तथा संपादन आईडी का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जन्म प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से सम्पर्क कर जन्म प्रमाण पत्र शत प्रतिशत बनाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 सीटर छात्रावास में शतप्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है। बच्चों के अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्रत्येक विकासखंड से कम से कम 10-10 विद्यार्थियों का प्रवेश करने और विद्यार्थियों का चिन्हांकन कर शतप्रतिशत प्रमाण पत्र बनाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयकों को दिये। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित दिव्यांग छात्रावास का समय- समय पर जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जावे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि समस्त विद्यालयों की कक्षाओं में अध्ययन के पश्चात पलायन कर चुके विद्यार्थियों की जानकारी ड्रॉप बॉक्स में संकलित करना सुनिश्चित करें। समस्त प्राचार्य एनएएसएस के लिए गंभीरता से कार्य करें। कमजोर बच्चों को चिन्हंकित कर वीडियो तथा ऑडियो के माध्यम से अध्यापन का कार्य कराया जावे। मॉक टेस्ट- एक के पश्न पत्र को हल कराते हुए विद्यार्थियों से अभ्यास कराया जावे। हिंदी व गणित विषय पर विशेष अध्यापन का कार्य कराया जावे। साथ ही कक्षा 9 वीं में एनएएस की तैयारी के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा सतत मॉनीटरिंग की जावे। एनएएस की तैयारी के लिए विद्यालयवार, प्रश्नवार डाटा तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने एमपी टॉस्क छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि छात्र- छात्राओं के एमपी टॉस्क पोर्टल पर शतप्रतिशत पंजीयन का कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे विद्यार्थी जिनकी प्रोफाईल नहीं बनाई गई है, उन विद्यार्थियों की जानकारी 25 नवम्बर तक सुचीबद्ध कर प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त प्राचार्यों को दिये। उन्होंने सीडब्ल्यूएसएन छात्रों का राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल- एनएसपी पर शतप्रतिशत पंजीयन का कार्य किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिये।

रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी

निर्धारित शर्तों का करना होगा पालन
नरसिंहपुर। जबलपुर डिवीजन के इटारसी- जबलपुर खंड पर रेलवे लेबल क्रॉसिंग नंबर 265, 267, 268, 269 व 270 के लिए अंडरब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के पूर्व रेलवे लेबल क्रॉसिंग बंद करने और करेली- बोहानी रेलवे खंड के मध्य स्थित समपार फाटक क्रमांक 263 पर रोड ओवर ब्रिज बन जाने के पश्चात बंद करने के लिए कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल ने निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडवारा के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभिन्न शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है। जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार जिन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, उनमें ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान रेलवे फाटक बंद नहीं किया जावे, यदि फाटक बंद किया जा रहा है, उस स्थिति में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जावे।

गुरुवार को पलकमती नदी राज्य मार्ग पर लगा जाम, प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनाई पक्ष-विपक्ष को खरी-खोटी

हीरालाल गोलांनी सोहागपुर। सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र निर्मित होने के बाद क्षेत्र की जनता-जनार्दन को लग रहा था कि क्षेत्र की विकराल समस्याओं से निजात मिल जाएगा। लेकिन सब मुंगेरीलाल के सपने ही लोगों ने देखें हैं। हालांकि कुछ नवधनाद्यों की संख्या वरदहस्त के कारण बढ़ गई है।जो हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। अब बात की जाए नगर के मध्य बसे सोहागपुर की। बरसों से नर्मदापुरम पिपरिया राज्य मार्ग 22 के पलकमती नदी पुल लगने वाले जाम की। यहाँ आए दिन जाम की स्थिति बनना सामान्य बात है। लेकिन यदि सोहागपुर में बाजार का दिन गुरुवार आ जाए तो जाम से जुझते लोग कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते।आज भी पलकमती नदी पुल से हार्वेस्टर निकले के चक्कर में करीबन आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। रघुवंशीपुरा से लेकर एस एस मार्ट तक वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं। जिसमें चार पहिया वाहन,



विधायक के भाई ने अत्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा पर विधायक और प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगती

नर्मदापुरम। नगर में हत्या, मार-पीट, झगड़ा सट्टा, अवैध शराब बिक्री जा रही चरम सीमा पर है। जो विगत तीन वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। परंतु हमें उस पर कुछ नहीं कहना। आवागमन सुचारू रूप से हो सके इसके लिए पुलिस पर यदि कोई जवाबदारी हो तो सक्षम कार्यवाही करवाने का कष्ट करें। हम आपके व्यक्तिगत एहसान मंद रहेंगे। यह पत्र पुलिस अधीक्षक को लिखकर विधायक के बड़े भाई भवानी शंकर शर्मा ने फिर नगरीय कानून व्यवस्था की कलाई खोल कर सनसनी फैला दी। 22 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र के पीछे विधायक के बड़े भाई भवानी शंकर का उद्देश्य क्या है वे निशाना किस पर साध रहे इसे लेकर पुलिस महकमे में फिलहाल सुगुवागुहट तो तेज हो गई। विधायक के बड़े भाई पं भवानी शंकर के लिखे इस पत्र से तो झलक रहा कि, प्रशासनिक अधिकारियों पर विधायक की पकड़ नहीं..? लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि विधायक की प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ ढीली है। अगर ऐसा होता तो कलेक्टर के पास इतने अधिकार तो है



कि वो जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर नजूल शीट नं 43 के 15/1 जमीन नामांतरण करवाने के मामले में नर्मदा शिक्षा समिति प्रबंधक को कटघरे में खड़ा कर सके और पुलिस कप्तान के पास नर्मदा शिक्षा समिति प्रबंधक का वह अनुबंध पत्र तो होगा ही जिसमें एसएनजी

स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए दिए गए सरकारी अनुदान राशि का संस्था द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर विभाग ने अन्य संस्थाओं के साथ नर्मदा शिक्षा समिति से सरकारी पैसा वसूली के लिए आरआरसी जारी करने के लिए तहसीलदार को विभागीय पत्र लिखा था । बहरहाल फ़ैज अहमद किदवाई और प्रशांत मेहता जैसे दमदार कलेक्टर बहुत कम मैदान पर आ पाते हैं। पर यहां चिंता की बात यह है कि विधायक के बड़े भाई नगरीय व्यवस्था के लिए चिंता जता रहे और विधायक भाई सहित प्रशासन निश्चित है..! नगर में वाहन खड़े कर आवागमन रोकने बाबद पुलिस अधीक्षक को लिखी गई शिकायत पर इन बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने शनिवार 19 अक्टूबर को उनके साथ सड़क पर खड़ी घटना का जिक्र करते हुए

यातायात प्रभारी का भी जाम में फंसने का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा है कि अव्यवस्था से सभी पीड़ित व्यक्ति ज्यादातर चुप रहते हैं या न जाने क्यों हमसे शिकायत करते हैं अतः यह पीड़ा केवल हमारी नहीं अपितु पूरे शहर में रहने वाले अधिकांश नागरिकों की है।

विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आगामी 10 नवंबर को होगा आयोजन समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, युवाओं, बुजुर्गों का सम्मान करेगा ब्राह्मण समाज

बैतूल। जिले के ब्राह्मण समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का आगामी 10 नवंबर 2024 को सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही समाज में सक्रिय प्रतिभावान युवाओं, वरिष्ठजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। यह निर्णय सर्व ब्राह्मण समाज की सामूहिक बैठक में बुधवार को लिया गया। यह बैठक बुधवार की शाम दत्त मंदिर सविल लाइन बैतूल में आयोजित की गई। परशुराम भगवान और दत्तात्रेय भगवान के पूजन के साथ बैठक प्रारंभ हुई। इसके बाद बैठक के संयोजक पंडित कांतु दीक्षित एवं पंडित प्रमोद शर्मा ने बताया कि जिले के सर्व ब्राह्मण समाज संघटन के बैनर तले आगामी 10 नवंबर 2024 रविवार को दोपहर 2 बजे से द्वारका मैरिज लॉन, तिवारी पेट्रोल पंप के सामने, कालापाटा बैतूल में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में पंडित संजय पप्पी शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2024 में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान मेडल और प्रमाणपत्र से इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके अलावा समाज के ऐसे प्रतिभावान बच्चों एवं युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो या कला आदि अन्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। बैठक में पंडित ब्रजकिशोर टीटू पांडे ने बताया कि ऐसे वरिष्ठजनों को भी कार्यक्रम में बैच लगाकर



व प्रमाण पत्र देकर सम्मान करेंगे, जिन्होंने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो। उन्होंने बताया कि जिस तरह ब्राह्मण समाज की युवा विंग परशुराम सेना ने वर्ष 2017 में सभी को -बढ़ते कदम आवार्ड-देकर सम्मानित किया था। समाज द्वारा ठीक उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंडित नरेन्द्र शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने समाज के सभी लोगों से अपील की है कि वे आगामी 05 नवंबर तक ऐसे प्रतिभावान लोगों की जानकारी पंडित प्रमोद शर्मा (मोबा. 9425002656) पर आवश्यक रूप से पहुंचा देंवें। इसके बाद पंडित कांतु दीक्षित के नेतृत्व में समाज के 10 सदस्यीय वरिष्ठजनों के पैनल द्वारा उसका परिषण कर अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी। बैठक के

अंत में समाज के वरिष्ठ पंडित नरेंद्र शुक्ला ने बैठक के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया । बैठक में उपस्थित अन्य विप्र बहनों-बंधुओं ने अपने-अपने सुझाव भी रखे। बैठक में अन्य प्रमुख विप्र बंधु अंशु-बहनों में अशोक पयन मिश्रा, वीरेंद्र पालीवाल, संजय द्विवेदी, महेश शुक्ला, सलिल हरदास, आशीष पचौरी, अंशुल शुक्ला, राकेश रक्षू शर्मा, श्रीभाऊ देशपांडे, विक्रम शर्मा, राजा शर्मा, अंशुल मिश्रा, श्रीराम देव, दीपक पात्रीकर, अनिल दुबे, अनिरुद्ध दुबे, ओम द्विवेदी, प्रशांत साइबेडकर, कुणाल शर्मा, नंदिनी तिवारी, प्रेरणा शर्मा, तरुणा द्विवेदी, नीलम मिश्रा, तुलिका पचौरी, निमिषा शुक्ला, नीलू भावर्ग, स्मिता पत्रीकर सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित थे।

आयुर्वेद और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कल्याण पर जिले में हुआ कार्यक्रम का आयोजन

नरसिंहपुर। आयुष विभाग नरसिंहपुर द्वारा धनवंतरी दिवस के उपलक्ष्य में आयुर्वेद और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कल्याण पर जिले के सभी ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. सुरता सिंह चौहान ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत, कार्यस्थल पर आम स्वास्थ्य समस्यायें, आयुर्वेदिक तकनीक के माध्यम से थकान का प्रबंध, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, ध्यान और योग के माध्यम से तनाव संबंधी नवाचारों का क्रियान्वयन किया गया। कार्यक्रम के लिए डॉ. नमिता सोनी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन बालक उच्चतर माध्यमिक शाला गाडवारा, उत्कृष्ट विद्यालय चीचली, हई स्कूल बिलहरा, चांवरपाठा, पुलिस स्टेशन गोटोगांव, कृषि उपज मंडी करेली, पीएम श्री स्कूल एवं पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किये गये। कार्यस्थल पर तनाव मुक्ति प्रबंधन के लिए वाय ब्रेक व स्ट्रेस को कम करने के लिए डिमोस्ट्रेशन सूक्ष्म व्यायाम योग व स्ट्रीचिंग करवाई गई। कार्यक्रम में सभी ब्लॉक के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ व योग शिक्षक मौजूद थे।

